

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक संवत्) [संख्या 09

विषय-सूची हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0			रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति,)	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	9-10	975
स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	89—118		भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया) 1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणें के अभिनिर्णय भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण		975	(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा समाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	<u>.</u>	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	215—247	
तना खण्ड वनाजला प्रवावत		975	स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र		1425

भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4 विज्ञप्ति / नियुक्ति 08 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 1234 / दो-4-2023—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित / संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु० 77,840-1,36,520 (पुराना वेतनमान रु० 27,700-770-35090-920-40450-1080-44770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	लोक सेवा आयोग की सूची की क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता
1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
1	14	001722	AAKANKSHA MISHRA	श्री क्षेमेन्द्र मिश्रा	टीचर्स कॉलोनी फरेन्दा खुर्द, आनन्दनगर, जिला-महाराजगंज,
			आकांक्षा मिश्रा		ਚ0प्र0-273155
2	16	013239	SNIGDHA PRADHAN	श्री ओम नरायण प्रधान	661 सिद्धेश्वर नगर कॉलोनी वार्ड नं0-6, गाजीपुर, उ०प्र0-
			स्निग्धा प्रधान		233001
3	17	015339	SOMYA GUPTA	श्री संदीप गुप्ता	म0नं0-2 स्ट्रीट नं0-1, मॉडल
			सौम्या गुप्ता		टाउन, बहादुरगढ़, झज्झर, हरियाणा-124507
4	19	061552	NIVEDITA SINGH	श्री जय प्रकाश सिंह	जे-27 पेरामाउण्ट ट्यूलिप, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उ०प्र0-
			निवेदिता सिंह		247001
5	21	022444	ANKIT PAL	श्री कृष्ण बिहारी	3124 न्यू पटेल नगर, नियर
			अंकित पाल	पाल	गणेशधाम, उरई, जालौन, उ०प्र0-285001
6	23	071368	JYOTI SHARMA	श्री सतबीर शर्मा	384, ढाणी सरोगियान,नेहरू
			ज्योति शर्मा		पार्क के सामने, भिवानी, हरियाणा-127021
7	24	017712	NEERU ANAND	श्री संजीव	पी-10 367, नई बस्ती मिर्जापुर,
			नीरू आनन्द	कुमार आनन्द	लखनऊ, उ०प्र0-226031

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
8	26	048053	PRAJJAWAL AGRAWAL	श्री चैन सुख अग्रवाल	24, वार्ड नं0-8, मेन मार्केट, चम्पावत, उत्तराखण्ड-262309
			प्रज्जवल अग्रवाल		
9	30	019889	KASHISH AGGARWAL	श्री राजन अग्रवाल	1086 सेक्टर-17, हुडा, यमुनानगर, हरियाणा-135001
			कशिश अग्रवाल		
10	34	069001	YATAN KWATRA	श्री राकेश कुमार	362-7, संत नगर, पटियाला चौक, जिन्द, हरियाणा-126102
			यतन कवात्रा		
11	36	022623	AKSHI GILL	श्री छेत्रपाल सिंह गिल	मुंजाल पी जी, सी-301, ब्लॉक-
			अक्षि गिल	।तह ।गल	सी, सूरजमल विहार ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110092
12	40	035909	KIRTI MISHRA	श्री राजीव	268ए, के ब्लॉक, यशोदा नगर,
			कीर्ति मिश्रा	कुमार मिश्रा	यशोदा नगर, कानपुर नगर, उ०प्र0-208011
13	49	026564	ANKITA	श्री अजय कुमार	अशोक नगर, नियर ए.पी
			अंकिता		कॉलोनी, गया, बिहार-823001
14	54	016444	ANKIT	श्री राजिन्दर ——	282, राम नगर, अम्बाला,
			अंकित	कुमार	हरियाणा-134003
15	60	018164	ANKIT KAUSHIK	श्री रमा शंकर	ललिता शर्मा, ए-1001, गोल्फ
			अंकित कौशिक	शर्मा	एवेन्यू-1, सेक्टर 75, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र0-201301
16	70	001805	ARPIT TYAGI	श्री प्रमोद कुमार	सत्ताली पट्टी, ग्राम व पोस्ट-
			अर्पित त्यागी		नवाला, जिला-मुजफ्फरनगर, उ०प्र0-251201
17	74	032318	SHIVANI	श्री राजेश	पवन राय, 23/47/137,
			शिवानी	यादव	किदवई नगर नियर ओल्ड साकेत हॉस्पिटल, अल्लापुर, प्रयागराज, उ०प्र0-211006
18	75	040032	NIKITA SINGH	श्री रनवीर सिंह	म0नं0-27 शीतला धाम कॉलोनी,
			निकिता सिंह		दयालबाग, आगरा, उ०प्र0- 282005

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
19	82	050813	PRAKHAR TIWARI प्रखर तिवारी	श्री अरविन्द कुमार तिवारी	27, डी ब्लॉक, संता सोसायटी, रामपुरम, श्यामनगर, कानपुर नगर, उ०प्र0-208013
20	87	025244	ANKIT TIWARI अंकित तिवारी	श्री अशोक कुमार तिवारी	1964 I ब्लॉक 11 एवेन्यू, गौर सिटी 2, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र0-201309
21	88	004993	PARVEEN परवीन	श्री सुरेश	एफ 26ए / एफ ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, सिंगल स्टोरी, विजय नगर, नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली- 110009
22	93	009789	KANISHK RATHAUR कनिष्क राठौर	श्री उमेश चन्द्र राठौर	नरेश चन्द्र गुप्ता, 2 / 10 नियर सुनहरी मस्जिद नियर टण्डन गारमेण्ट्स, फर्रुखाबाद, उ०प्र0- 209625
23	96	061340	VANSHIKA SRIVASTAVA वंशिका श्रीवास्तव	श्री सोहन लाल श्रीवास्तव	सी-1156, सेक्टर-4, बसन्त खण्ड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, उ०प्र0-226010
24	98	059635	RENU GAUTAM रेनू गौतम	श्री नन्हें राम	445 / 515, विश्वास नगर, ठाकुरगंज, चौक, लखनऊ, उ०प्र0-226003
25	103	017392	NEERAJ YADAV नीरज यादव	श्री विजय बहादुर यादव	विष्णुपुर, रानीगंज, प्रतापगढ़, उ०प्र0-230304
26	114	052141	VIVEK DUBEY विवेक दूबे	श्री सुभाष चन्द दुबे	ग्राम-सबया, पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर, उ०प्र0-274402
27	119	007008	HARSHDA GANGWAR हर्षदा गंगवार	स्व0 जयन्त कुमार	सावित्री गंगवार, 144, पटेल पुरम, फर्रूखाबाद, उ०प्र0- 209502
28	124	023068	HIMANSHU NAUTIYAL हिमांशु नौटियाल	श्री अशोक कुमार	ग्राम-बलालबेड़ी अम्बेहटा, पोस्ट- नकुड, जिला-सहारनपुर, उ०प्र0- 247340
29	127	028258	SHIVAM YADAV शिवम यादव	श्री प्रेम शंकर यादव	आशा स्मृति विला, नियर माधी देवी मन्दिर, रायबरेली, उ०प्र0- 299001

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
30	129	039388	ISHANT JAISWAL	श्री सुनील कुमार	62 / 177 हरबंश मोहाल, कानपुर नगर, उ०प्र0-208001
			ईशांत जायसवाल	जायसवाल	
31	134	016779	SONAL SAHU सोनल साहू	श्री पुरूषोत्तम दास साहू	64 / 21ए गडरिया मोहाल, कानपुर नगर, उ०प्र०-208001
32	136	043050	MAMTA YADAV ममता यादव	श्री रमेश यादव	298 सेक्टर-ए, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, शान्तिपुरम, फाफामऊ, प्रयागराज, उ०प्र0-211021
33	138	043747	GARIMA ARYA गरिमा आर्य	श्री सत्य ब्रह्म	म0नं0-417, ग्राम-दतियाना, पोस्ट-दतियाना, 12 मुजफ्फरनगर, उ०प्र0-251001
34	139	001447	DHEERAJ VERMA	श्री ओम प्रकाश वर्मा	श्री नगर कॉलोनी, खूबपुर, नियर जी के ग्राण्ड, सीतापुर, उ०प्र0-
			धीरज वर्मा		261001
35	142	024292	NEHA KUMARI BIND	श्री रामलखन	डी 64 / 14 एम-1, माधवपुर सिगरा, वाराणसी, उ०प्र0-
			नेहा कुमारी बिन्द		221010
36	146	038435	RATANJEET JAISWAL	श्री बृज नारायण प्रसाद	पडरौना, साहबगंज साउथ मालवीय नगर पडरौना,
			रतनजीत जायसवाल	जायसवाल	कुशीनगर, उ०प्र0-274304
37	148	003464	ANIND UMRAO अनिन्द उमराव	श्री विनोद कुमार उमराव	एच-176, वर्ल्ड बैंक कॉलोनी बर्रा, कानपुर नगर, उ०प्र0- 208027
38	149	015597	SARVESH KUMAR PANDEY	श्री शशि भूषण पाण्डेय	17, ग्राम-भिलोरा बुजुर्ग, पोस्ट- नौसाढ़, जिला-गोरखपुर, उ०प्र0- 273016
			सर्वेश कुमार पाण्डेय		210010
39	153	041298	SHIVESH RAJ JAISWAL	श्री मृत्यंजय प्रसाद	आनन्द हॉस्पिटल, म0नं0-254-1, लॉट नं0-2, जायसवाल स्कूल
			शिवेश राज जायसवाल		रोड, हनुमानपुर, चन्दौली, उ०प्र0-232101
40	156	071534	RAJ VARDHAN TIWARI	श्री अरविन्द कुमार तिवारी	1093 / 84ए, राजीव विहार चंदीपुरवा, एन० एच० रोड
			राज वर्द्धन तिवारी		एस०ओ०, नौबस्ता, कानपुर नगर, उ०प्र०-२०८०२१

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		-
41	159	005062	AANCHAL MALIK	श्री नरेन्द्र कुमार मलिक	अंजू मलिक, जी० पी0-06, डिवाइंडर रोड, गंगानगर मेरठ,
			आंचल मलिक		ਚ0ਸ0-250001
42	160	071493	PRATIBHA SINGH	श्री विन्द्रा सिंह	ग्राम-महेशपुर, पोस्ट-लालपालपुर, जिला-हरदोई, उ०प्र0-241001
			प्रतिभा सिंह		
43	164	049810	MANISH KUMAR	श्री पल्टू राम	एम-203, सेलिब्रिटी ग्रीन, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ, उ0प्र0-
			मनीष कुमार		226030
44	173	045396	SAKSHI CHAUDHARY	श्री नरेन्द्र कुमार	मोहल्ला-रामलीला (चौधरीयान), करबा-झालू, जिला-बिजनौर,
			साक्षी चौधरी		ত্ত0স0-246728
45	174	040425	ASHUTOSH SHUKLA	श्री बी0 के0 शुक्ला	खोजनपुर, कन्टोनमेन्ट पोस्ट ऑफिस, अयोध्या, उ०प्र०-
			आशुतोष शुक्ला		224001
46	175	012536	ROHIT YADAV	श्री कृष्ण लाल	गवर्नमेंट रेजीडेन्स नं0-213
			रोहित यादव	यादव	टाइप २, तेज बहादुर सप्रु हॉस्पिटल, कैम्पस, प्रयागराज, उ०प्र0-211002
47	177	032874	PRIYANSHI YADAV	श्री बीरेन्द्र कुमार यादव	ओल्ड स्कूल बिल्डिंग, सी0एस0ए0, यूनिवर्सिटी कैम्पस
			प्रियांशी यादव		नवाबगंज, कानपुर नगर, उ०प्र0-208002
48	178	019521	VIMMY SINGH	श्री चन्द्र पाल	392 सी०डब्ल्यू० २, बसंत विहार
			विम्मी सिंह	सिंह	नौबस्ता कानपुर, कानपुर नगर, उ०प्र0-208021
49	179	031634	PRIYANKA YADAV	श्री पवन कुमार	116 आर0 ए0 बाजार न्यू कैण्ट, आर0 ए0 बाजार, प्रयागराज,
			प्रियंका यादव		ਚ0ਸ਼0-211001
50	180	048042	ADESH KUMAR SRIVASTAVA	श्री रत्नेश कुमार श्रीवास्तव	ग्राम-कौलापुर, पोस्ट ऑफिस- गोपीगंज, जिला-संत रविदास
			आदेश कुमार श्रीवास्तव		नगर, उ०प्र0-221303

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
51	182	077668	KAJAL SRIVASTAVA	श्री अश्वनी श्रीवास्तव	राहुल गैस गोदाम, भिटारी लोहता रोड, वाराणसी, उ०प्र०-
			काजल श्रीवास्तव		221107
52	183	007308	HARSHIT AGARWAL	श्री संजय कुमार अग्रवाल	भारत पुस्तक भण्डार, बाजार गंज, नगीना, बिजनौर, उ०प्र0-
			हर्षित अग्रवाल		246762
53	184	026108	HIMANSHU VERMA	श्री अनिल कुमार वर्मा	जैस राम वर्मा, ग्राम-रायभानपुर, पोस्ट-बनी, तहसील-जयसिंहपुर,
			हिमांशु वर्मा		जिला-सुलतानपुर, उ०प्र०- 228131
54	185	021043	AKSHAY KUMAR	श्री दशरथ सिंह	220 कटरा नदीगांव, पोस्ट- नदीगांव, जालौन, उ0प्र0-
			अक्षय कुमार		285206
55	186	004002	AAKRITI PRAKASH	श्री ओम प्रकाश भट्ट	संगम अपार्टमेंट, जी0 एफ0-1, 466 / 362 न्यू ममफोर्डगंज,
			आकृति प्रकाश		सुभाषनगर, प्रयागराज, उ०प्र०- 211002
56	188	032399	STUTI SONKER	श्री घनश्याम	15 / 8ए, ड्रमण्ड रोड, टी०वी०
			स्तुति सोनकर	सोनकर	टावर के सामने, प्रयागराज, उ०प्र0-211001
57	189	049238	SHREY KUMAR VERMA	श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा	502 / 133, मुकरिम नगर नियर मनकामेश्वर मंदिर, डालीगंज,
			श्रेय कुमार वर्मा	Ç	लखनऊ, उ०प्र0-226020
58	190	031149	KHUSHBOO SHARMA	श्री अनिल कुमार शर्मा	रमेश चन्द्र उपाध्याय, श्री मोहनलाल आदर्श इण्टर
			खुशबू शर्मा	3	कॉलेज, सलेमपुर रोड, हाथरस, उ०प्र0-281306
59	191	048861	VISHNU VERMA	श्री प्रेम वर्मा	317/8/1 पीली कोठी,
			विष्णु वर्मा		शिवकुटी, प्रयागराज, उ०प्र0- 211004
60	193	075058	SHWETA	श्री मनोज	04 शक्ति पुरम कॉलोनी, गुप्ता
			KASHYAP श्वेता कश्यप	कश्यप	प्रोविजन स्टोर नियर डायमण्ड सिनेमा रोड, रामपुर, उ०प्र०-
					244901

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
61	194	017586	BRIJENDRA SWAROOP	श्री साहब लाल	126 गोठवारा, मिल्कीपुर, अयोध्या, उ०प्र0-224127
			बृजेन्द्र स्वरूप		
62	195	033516	SACHIN SINGH सचिन सिंह	श्री धनपाल सिंह	ग्राम-लखवाया रोहटा रोड, जिला-मेरठ, उ०प्र0-250005
63	196	035532	NIHARIKA YADAV	श्री राधे श्याम यादव	सी-40 दूरभाष नगर, आई0 टी0 आई0 कॉलोनी एलटीडी,
			निहारिका यादव		रायबरेली, उ०प्र0-229010
64	197	064491	MUNI KUMAR SINGH	श्री अवधेश कुमार सिंह	880 के, संगीत सदन, खुशवक्तराय नगर, झाऊपुर,
			मुनि कुमार सिंह		फतेहपुर, उ०प्र0-212601
65	198	065763	ANAMIKA	श्री जयपाल	ग्राम-पटवाई, पोस्ट-पटवाई,
			अनामिका	सिंह	तहसील-शाहाबाद, जिला-रामपुर, उ0प्र0-244901
66	199	067183	ANAMIKA SINGH	श्री बजरंगी सिंह	एस ए-17 / 278 के-3 सारंग तालाब पहाडिया, नक्खीघाट
			अनामिका सिंह		वाराणसी, उ०प्र०-221007
67	200	031661	VIPASHA GHANGORIA	श्री कुमार उमेश	प्रेम कॉटेज, 534-18, जनपथ रोड, अलीगंज, लखनऊ, उ०प्र0-
			विपाशा गंगोरिया		226024
68	201	036978	SHIVANI SINGH	श्री राजेश	160 नरसीपुरम कालोनी रोंची
			शिवानी सिंह	कुमार	बांगर, बाद, मथुरा उ0प्र0- 281006
69	203	011560	SWATI YADAV	श्री बुद्धिराम	कांदीपुर, पो०-कटघर मूसा,
			स्वाती यादव	यादव	अम्बेडकर नगर, उ०प्र०-224186
70	204	044138	SHOBHA RANI	श्री वेद प्रकाश	म0नं0-475 साहूजी नगर नियर
			शोभा रानी	सागर	डैफोडिल स्कूल, गली नं0-3, वार्ड-9, रामपुर, उ०प्र0-243703
71	205	015431	MOHAMMAD	श्री मोहम्मद	2/51, विभव खण्ड, गोमती
			ADIL ANSARI	असलम अंसारी	नगर, लखनऊ, उ०प्र0-226010
			मोहम्मद आदिल अंसारी		

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
72	206	023390	LAVLESH KUMAR	श्री राम बाबू सिंह	126, काशीपुर, सम्भल (भीम नगर), उ०प्र०-243722
			लवलेश कुमार		
73	207	046624	ANUBHAV JAISWAL	श्री विजय कुमार	851-सागर मेडिको, खोया मण्डी, नियर आर्य समाज मन्दिर,
			अनुभव जायसवाल	जायसवाल	रायबरेली, उ०प्र०-229001
74	208	014182	ABHAY DEEP VISHWAKARMA	श्री विशुन राम विश्वकर्मा	ग्राम व पोस्ट-बनवीरपुर, थाना- फूलपुर, तहसील-निजामाबाद,
			अभय दीप विश्वकर्मा		जिला-आजमगढ़, उ०प्र०-276304
75	209	019468	HIMANSHI SONKER	श्री अमृत लाल सोनकर	587, मुठ्ठीगंज, प्रयागराज, उ०प्र0-211003
			हिमांशी सोनकर		
76	210	010994	PRINCE	श्री अनिल	ग्राम-ललियाना, पोस्ट-ललियाना,
			प्रिंस		जिला-बागपत, उ०प्र०-२५०५१५
77	211	042835	RAVI KANT YADAV	श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव	937, प्रज्ञा नगर कॉलोनी, हीरामनपुर, वाराणसी, उ०प्र0-
			रवि कांत यादव		221007
78	213	045616	SAKSHI DHAMA साक्षी धामा	श्री संजीव कुमार	म0नं0-47 पटृटी गिरिधरपुर नेहरू नगर, खेकड़ा, बागपत, उ0प्र0-250101
79	214	026895	RAMESH SINGH रमेश सिंह	श्री श्रीपति सिंह	ग्राम-खैरवा, पोस्ट-कोपिया, जिला-संत कबीर नगर, उ०प्र०- 272199
80	215	017456	RUBY रूबी	श्री संग्राम सिंह	717, सेक्टर-7, जागृति विहार, मेरठ, उ०प्र0-250004
81	216	024820	TARUN KUMAR SINGH	श्री प्रेमजीत कुमार सिंह	888ए / 526ई / 5ए, उचवा गढ़ी, राजापुर, प्रयागराज, उ०प्र0-
			तरूण कुमार सिंह	-	211002
82	217	013083	AKHIL CHOUDHARY	श्री संजीव चौधरी	सी-12, कावेरी इन्क्लेव, मोदीपोन रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद,
			अखिल चौधरी		ਚ0ਸ0-201204
83	219	057985	AVINASH MAURYA	श्री रामदास मौर्य	उत्तर पट्टी, पुरवा, संत कबीर नगर, उ०प्र0-272271
			अविनाश मौर्या		

CHAUDHARY चौधरी र	नैट नं0-405, विक्ट्री हाइट्स रेजीडेन्सी, अनूपशहर रोड, अलीगढ़, उ०प्र0-202122
CHAUDHARY चौधरी र	रेजीडेन्सी, अनूपशहर रोड, अलीगढ़, उ०प्र0-202122
मो० आसिम चौधरी	• •
	TO TO 405 A THE TOTAL
5	न0नं0-125 बी, पॉकेट एल, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिल्ली-110095
)नं0-651, सेक्टर-6, जागृति वेहार, मेरठ, उ०प्र0-250004
सुधीर कुमार निर्मल हि	म-पूरे महिपाल सिंह, पोस्ट- थेगवां, तहसील-कुंडा जिला- प्रतापगढ़, उ०प्र0-230201
रिंम सिंह सिंह म	गॅक-जी, फ्लैट नं0-एस ∕ 2, हेन्द्र इन्क्लेव, शास्त्री नगर, गाजियाबाद-उ0प्र0-201002
	10नं0-1, नियर शिव मन्दिर ामपुर रामराज, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251320
90 230 033623 AMAN DEEP श्री प्रेम शंकर अमन दीप सरे	नीरज कुमारी, भटगांव, ोजनीनगर, लखनऊ, उ0प्र0- 226401
VERMA वर्मा	डिटोरियम के पीछे, सिविल लाइन्स, फतेहपुर, उ०प्र0- 212601
	ग्राम व पोस्ट-बर्थरा खुर्द, चौबेपुर, वाराणसी, उ०प्र0- 221104
SHARMA शर्मा पार्व	101, ब्लॉक-ए, रोड नं0-2, ती मेंसन लतमा रोड हटिया,
	रांची, झारखण्ड-834003
94 238 041674 PUSHPENDRA श्री दुर्गा प्रसाद KUMAR गौतम GAUTAM	62 के-4-1बी, राजापुर, प्रयागराज, उ०प्र0-211001
पुष्पेन्द्र कुमार गौतम	

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
95	239	019543	AKSHAT SONKAR	श्री गिरीश चन्द्र	284, सेक्टर-4 / 94बी / 8, काला डांडा, हिम्मतगंज, प्रयागराज,
			अक्षत सोनकर		ਚ0ਸ0-211016
96	241	047794	RADHIKA RAJ राधिका राज	श्री गौतम कुमार	सेक्टर-14, म0नं0-321, बरौली खलीलाबाद, वृन्दावन योजना, नियर उतरेटिया, रेलवे क्रासिंग, लखनऊ, उ0प्र0-226016
97	242	016330	KUSUM VERMA	श्री माया राम	ए-2, ऑरेंज विला दरोगा खेड़ा,
			कुसुम वर्मा		कानपुर रोड, लखनऊ, उ०प्र०- 226008
98	243	059746	DEEPIKA RANI	श्री कमल सिंह	मामचन्द लाम्बा, म0नं0-
			दीपिका रानी		2सी / 579, मलहीपुर रोड, सहारनपुर, उ०प्र0-247001
99	244	053204	ANUKRITI	श्री दिनेश	1/11/94 बढ़ई का पुरवा
			RAWAT अनुकृति रावत	कुमार	सहादतगंज, अयोध्या, उ०प्र०- 224001
100	246	025814	PRIYANKA	श्री अनिल	फ्लैट नं0-टी-सुखमणि अपार्टमेंट,
			GAUTAM	कुमार गौतम	प्लॉट नं0-888, बी ब्लॉक,
			प्रियंका गौतम		पनकी, कानपुर नगर, उ०प्र०- 208020
101	247	003427	DHIRENDRA KUMAR	श्री कमलेश	1बी सादियाबाद बड़ा बघाड़ा, ১० :
			SONKAR	चन्द्र सोनकर	तेलियरगंज, प्रयागराज, उ०प्र०- 211004
			धीरेन्द्र कुमार सोनकर		
102	249	053351	MONU	श्री शौकीन	ग्राम व पोस्ट-करवारा, ब्लॉक-
			मोनू		बघरा, जिला-मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251001
103	251	017948	HIMANI	श्री विनोद	विनोद कुमार मैनेजर, इन्दिरा
			GAUTAM हिमानी गौतम	कुमार	कॉलोनी, राजन नगला भोलेपुर, फर्रुखाबाद, उ०प्र0-209601
404	050	050704		ਅੀ ਜ਼ੜਿਤ ਤਾਨਾ	
104	252	050761	VISHWANATH विश्वनाथ	श्री रविन्द्र नाथ	म0नं0-21, गली नं0-8, विष्णुपुरी कॉलोनी नियर सिटी स्टेशन,
					हाथरस, उ०प्र०-२०४१०१

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
105	253	006744	ANJALI अंजलि	श्री शंकरलाल	एच0 आई0 जी0-II, 113 स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़, उ०प्र0-202001
106	254	061072	NITYANAND TYAGI	श्री संजय कुमार	ग्राम व पोस्ट-सेवटा, जिला- आजमगढ़, उ०प्र0-276128
			नित्यानन्द त्यागी		
107	255	003732	NAVEEN KUMAR	श्री गंगा महेश	12-1 टाइप-3 पी0 डब्ल्यू0 डी0 कॉलोनी, जेल रोड, बंगला
			नवीन कुमार		बाजार, लखनऊ, उ०प्र0-226002
108	256	059810	MANJU मंजू	श्री नेत्रपाल	253, नगला हुकुम सिंह, करौली बांगर, गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र0- 203209
109	257	072180	VIBHA विभा	श्री राम सजीवन	एल एस-2 / 680, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ, उ०प्र0- 226021
110	258	000817	SANKALP PANDEY	स्व० आनन्द कुमार पाण्डेय	एम 3/885, सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, आशियाना,
			संकल्प पाण्डेय		लखनऊ, उ०प्र0-226012
111	261	071128	JYOTI SAGAR ज्योति सागर	श्री दीप चन्द सागर	मधुबन वाटिका विजय नगर, पोस्ट-गोविन्दपुरी, गाजियाबाद, उ0प्र0-201201
112	262	000463	AKANKSHA PIPIL	श्री गुलाब सिंह	29 मोहल्ला-सुलतान नगर, जिला-ज्योतिबा फुले नगर,
			आकांक्षा पिपिल	0	ਚ0ਸ0-244235
113	263	036658	SHIVANI SINGH शिवानी सिंह	श्री यशपाल सिंह	A-1 दून एन्क्लेव, सेवला कलान, चन्द्रबनी रोड, मजरा, देहरादून-248171
114	264	027772	NEHA SINGH नेहा सिंह	श्री जगवीर सिंह	1906, रतनखण्ड, शारदा नगर, लखनऊ, उ०प्र0-226002
115	265	017898	SHIV SHANKAR DOHARE शिव शंकर दोहरे	श्री राम रतन दोहरे	02, वार्ड नं0-5, मोहल्ला- मुफ्तीटोला विशुनपुर टीला राधे श्याम मंदिर, कन्नौज, उ०प्र0- 209725

1	2	3	4	5	6
116	267	025554	(सर्वश्री / सुश्री)— PRIYANKA	श्री वीरसेन	पूर्वी लखपेडा रामलीला कालोनी,
			DIWAKAR प्रियंका दिवाकर		मोहम्मदी, लखीमपुर, उ०प्र0- 262804
117	268	062435	RICHA CHAUDHARY रिचा चौधरी	श्री जेo बीo चौधरी	371 ए, हिन्द नगर, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ0प्र0-226012
118	269	066042	AJAY KUMAR अजय कुमार	श्री राम स्वरूप	ईएसआई 642, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ, उ0प्र0-226021
119	270	023932	NEHA KESHLA नेहा केसला	श्री रमेश चन्द	मोहल्ला-नन्दू प्रसाद शामली, शामली (प्रबुद्ध नगर), उ०प्र0- 247776
120	272	003027	DHIRENDRA KUMAR	श्री राम करन	एन० एन० ०३/९८५, विज्ञान खण्ड, गोमती नगर, कान्हा विहार, लखनऊ, उ०प्र०-२२६०१०
121	274	025863	धीरेन्द्र कुमार ALKA BHARTI अल्का भारती	श्री ओम प्रकाश	58ई / 8एम / 1 गंगा नगर, राजापुर, प्रयागराज, उ०प्र०- 211001
122	275	039992	NIKITA SINGH निकिता सिंह	श्री विमल प्रकाश	117एल / 127, श्री कृष्ण धाम अपार्टमेंट, फ्लैट नं0-5, नवीन नगर काकादेव, कानपुर नगर, उ0प्र0-208025
123	278	051501	VIVASVAN PRAKASH विवस्वान प्रकाश	श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव	404 / बी, बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, प्रयागराज, उ०प्र0- 211006
124	279	025716	S ANAND एस आनन्द	श्री सहस्रनाम	ए 2-502, जागृति विहार आवास योजना कालिंदीपुरम, प्रयागराज, उ0प्र0-211012
125	280	071899	SURBHI SINGH सुरभि सिंह	श्री धर्मवीर सिंह	बी-37 / 188-ए, बिरदोपुर, महमूरगंज, वाराणसी, उ०प्र0- 221010
126	281	041461	VISHAL DIXIT विशाल दीक्षित	श्री भगवत शरण दीक्षित	51 सन सिटी फेज-1, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली, उ०प्र0- 243002

1	2	3	4	5	6
			(सर्वश्री / सुश्री)—		
127	283	026057	SATYENDRA KUMAR MISHRA सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	श्री भगवत कुमार मिश्रा	213 नियर एन0 एस0 एस0 स्कूल, कृष्णा नगर, जनौरा, अयोध्या, उ०प्र0-224001
128	284	031317	SAURABH KUMAR सौरभ कुमार	श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव	डी-706 एस जी ग्राण्ड सोसाइटी, राजनगर विस्तार, गाजियाबाद, उ०प्र0-201003
129	288	043980	URFI AZMI उर्फी आजमी	श्री कल्बे हुसैन आजमी	ग्राम-अइन्या, पोस्ट-बद्दोपुर, जिला-आजमगढ़-276125
130	289	006961	VIKAS KUMAR विकास कुमार	स्व0 तुलाराम सिंह	97 / 18, प्रकाश नगर, बीना प्रकाश हॉस्पिटल के सामने, बिजनौर, उ०प्र0-246701
131	290	031785	ASHISH TRIPATHI	श्री बासुदेव प्रसाद त्रिपाठी	कलन्दरपुर चौबे, पठवालिया, गोण्डा, उ०प्र0-271001
132	292	040865	आशीष त्रिपाठी ASHUTOSH SINGH आशुतोष सिंह	श्री चन्द्र हंस सिंह	म0नं0-296ए / 1 जे बी, न्याय विहार कॉलोनी, सेक्टर-3, गंगा द्वार, प्रयागराज, उ०प्र0-211015
133	293	009342	AASTHA DWIVEDI आस्था द्विवेदी	श्री अजय कुमार द्विवेदी	11-डी स्ट्रेची रोड, सिविल लाइन, नियर हाइडिल कॉलोनी, प्रयागराज, उ०प्र0-211001
134	299	005459	SIDHINATH SINGH SENGAR सिद्धिनाथ सिंह सेंगर	श्री सी पी सिंह	378 जवाहरपुरम मंगला विहार- 1, न्यू पी०ए०सी० लाइन, कानपुर नगर, उ०प्र0-208015
135	301	021561	VINAY KUMAR CHAHAR विनय कुमार चाहर	श्री दौलत राम चाहर	73 / बी, मनोहर धाम कॉलोनी, आगरा ग्वालियर रोड, इटोरा, आगरा, उ०प्र0-282001

^{2—} उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से, डाo देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव।

न्याय विभाग

अनुभाग-3 (नियुक्तियां) अधिसूचना

निरस्तीकरण

17 मई, 2023 ई0

सं0 डी-374 / सात-न्याय-3-2023-924(64) / 1990—चूँकि श्री मो0 नईम सिद्दीकी, नोटरी, तहसील राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र को मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सोनभद्र द्वारा सत्र परीक्षण संख्या- 132 / 2004 अ0सं0-186 / 2004 में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा दस वर्ष के सश्रम कारावास से दिण्डत किया गया है। अतः उनका नोटरी प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है।

अतएव नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-10 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि मो0 नईम सिद्दीकी का नाम नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी रजिस्टर से काट दिया जाय।

> आज्ञा से, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।

NYAY DEPARTMENT

Anubhag-3 (Appointment)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. D- 374/VII-Nyay -3-2023-924(64)/1990 Lucknow Dated 17 May, 2023 for general information.

NOTIFICATION

Cancellation

Dated 17 May, 2023

No. D-374/VII-Nyay-3-2023-924(64)/1990—WHEREAS Mr. Mohd. Naeem Siddiqui, Notary, Tehsil Robertsganj, District Sonbhadra has been sentenced to ten years rigorous imprisonment by the order dated 18-11-2020 passed by the Hon'ble Court, Additional Sessions Judge, Fast Track Court, Sonbhadra in Session Trial No. 132/2004 Crime No. 186/2004, so his notary certificate is cancelled.

THEREFORE in exercise of the powers under Section 10 of the Notaries Act, 1952, the Governor is pleased to order to remove the name of Shri Mohd. Naeem Siddiqui from the register maintained under Section 4 of the Notaries Act, 1952.

By Order,
Pramod Kumar Srivastava-II,
Principal Secretary,
Judicial & Legal Remembrancer.

विधान परिषद् सचिवालय

विज्ञप्ति

सेवानिवृत्ति

31 मई, 2023 ई0

सं0 1573 (अधिष्ठान)/वि०प0—267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या-1195/(अधि0) वि०प0-267/84, दिनांक 24 मई, 2022 ई० के क्रम में श्री इरशाद हुसैन, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 मई, 2023 ई० के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो गये।

नियुक्ति

14 जून, 2023 ई0

सं0 1692 (अधिष्ठान) / वि0प0-347 / 84-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में रिक्त (डिप्टी मार्शल के स्थायी पद-वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44,900-1,42,400) में उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री आदित्य नारायण, सहायक मार्शल को डिप्टी मार्शल के स्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44,900-1,42,400) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से, डा० राजेश सिंह, प्रमुख सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

01 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 1974 / 12-1-2022-111 / 19 टी०सी०—उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 "ख" (विकास शाखा) में कार्यरत, श्री महेन्द्र सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-87) को पदोन्नित समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ०प्र० कृषि सेवा श्रेणी-1 (समूह-क) में उप कृषि निदेशक स्तर के पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 6,600 / — में पदोन्नित किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- श्री महेन्द्र सिंह की पदोन्नित मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1357 / 2022 राजित राम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3- श्री महेन्द्र सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से, डाo देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव।

गृह (पुलिस) विभाग

अनुभाग-9

अधिसूचना

28 जून, 2023 ई0

सं0 2839 / 6-पु0-9-2023—साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत सराय अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 22 सन 1867) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करके, राज्यपाल आवास इकाइयों के संचालन को विनियमित करने के लिए त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया का उपबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं—

उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियमावली, 2023

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियमावली, 2023 कही जायेगी।
 - (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
 - (3) यह विनियमावली समस्त प्रचलित परिनियमों और उनके विनियमों के अनुरूप पढ़ी जायेगी।
 - 2. परिभाषाएँ (1) जब तक विषय या सन्दर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में,
 - (क) "आवास इकाई" का तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठानों से है जिसमें उनके परिसर सिम्मिलित है, जो यात्रियों के आश्रय और आवास के लिए प्रयोग किये जाते हैं जिनमें समस्त होटल, रिसॉर्ट, अतिथि गृह, फार्म स्टे और अन्य समस्त ऐसी आवास इकाइयाँ सिम्मिलित हैं जिनका प्रयोग यात्रियों द्वारा आश्रय के लिए किया जाता है, किंतु इसमें राजकीय अतिथि गृह सिम्मिलित नहीं हैं,
 - (ख) "अधिनियम" का तात्पर्य सराय अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1867) से है,
 - (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य संबंधित क्षेत्र के मण्डलायुक्त से है,
 - (घ) "प्राधिकृत पदधारी" का तात्पर्य संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस विनियमावली के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी से है,
 - (ङ) "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो आवास इकाई के संचालन के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता हो और ऐसी आवास इकाई के वेतन रोल पर हो। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो अनन्य रूप से वचन के अनुसार मरम्मत या रख-रखाव, परिसर में माल के परिदान या अन्य समान संबंधों के लिए परिसर में स्थित हो,
 - (च) "स्थानीय प्रबंधन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो ऐसे प्रतिष्ठान के परिसर में कार्य प्रणाली की निगरानी के लिए किसी आवास इकाई के स्वामी द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त हो,
 - (छ) "पेट्रॉन" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या ग्राहक से है जो किसी आवास इकाई में रहने या ठहरने की सुविधा प्राप्त करता है,
 - (ज) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से है।
- (2) इसमें प्रयुक्त एवं अपरिभाषित किन्तु सराय अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1867) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।
- 3. ऑनलाइन पोर्टल का विकास—(1) आवास इकाई के रिजस्ट्रीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन वेब एवं मोबाइल एप्लीकेशन आधारित पोर्टल विकसित किया जायेगा।

- (2) ऊपर उल्लिखित पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया जायेगा।
- (3) इस तरह का पोर्टल विकसित करने के पश्चात् राज्य सरकार एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें पोर्टल का विवरण और उसके उपयोग के लिए अनुदेश अन्तर्विष्ट होंगे।
- 4. आवास इकाइयों को संचालित करने के लिए अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण—(1) ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी किये जाने के 30 दिवसों के पश्चात्, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कोई आवास इकाई संचालित नहीं होगी। उक्त को सुनिश्चित करने के लिए जिला मिजस्ट्रेट समस्त आवश्यक विधिक कार्यवाहियाँ करने हेतु सशक्त होगा।
- (2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के समय, आवेदक द्वारा शपथ-पत्र पर एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें यह उल्लेख किया जायेगा कि वह अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के उपबंधों का अनुपालन करेगा / करेगी।
- (3) पोर्टल पर (रिजिस्ट्रीकरण हेतु) आवेदन के दिनांक से 45 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी ऐसी इकाई को रिजिस्ट्रीकृत करेगा और रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा या अस्वीकृति के विनिर्दिष्ट कारणों को उल्लिखित करते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देगा। 45 दिनों की इस अविध के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करने में विफलता को डीम्ड (मानित) रिजिस्ट्रीकरण समझा जायेगा और रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पोर्टल पर स्वचालित रूप से जारी कर दिया जायेगा।
- (4) उक्त आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दायर कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (5) प्रत्येक अस्वीकृत आवेदन के लिए विहित प्राधिकारी को अस्वीकृति के कारणों को मण्डलायुक्त को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- **5. आवास इकाईयों के लिए अनिवार्य अनुपालन**—(1) आवास इकाई को प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विहित प्राधिकारी द्वारा जारी रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करना होगा।
- (2) आवास इकाई किसी भी परिस्थिति में किसी पेट्रॉन को फ्रंट डेस्क पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त किये और अभिलेखों में प्रविष्ट किए बिना रहने की सुविधा का उपभोग करने की अनुज्ञा नहीं देगी—
 - (क) सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति,
 - (ख) पेट्रॉन का नाम, आयु और पता,
 - (ग) अतिथि से एक वचन-पत्र कि वह परिसर में कोई खतरनाक पदार्थ या कोई अवैध हथियार नहीं लाया है/लायी है।
- (3) आवास इकाई किसी आगंतुक या पेट्रॉन के अतिथि को फ्रंट डेस्क पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त किये और अभिलेखों में दर्ज किए बिना ठहरने के कमरें / रहने की सुविधा क्षेत्र तक पहुंचने की अनुज्ञा नहीं देगी—
 - (क) अतिथि/आगंतुक के सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति,
 - (ख) संबंधित पेट्रॉन के नाम के साथ अतिथि/आगंतुक का नाम, आयु और पता,
 - (ग) आगमन और प्रस्थान का समय।
 - (4) आवास इकाई, पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किए बिना किसी को सेवायोजित नहीं करेगी।
- (5) आवास इकाई को प्रवेश / निकास बिंदुओं, फ्रंट डेस्क और पार्किंग क्षेत्रों में सी०सी०टीवी कैमरे स्थापित कराना होगा और कम से कम 30 दिनों के लिए सी०सी०टी०वी० फुटेज को बनाये रखना होगा।
 - (6) आवास इकाई को 02 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित अभिलेखों को अनुरक्षित करना होगा—

- (क) पेट्रॉनगण का विवरण (उनके नाम, आयु, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण-पत्र संख्या और चेक इन-चेक आउट दिनांक के साथ पता)।
- (ख) समस्त कर्मचारियों के विवरण (उनके नाम, आयु, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण-पत्र संख्या और पता)।
- (7) आवास इकाई, निरीक्षण के समय या अन्यथा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधारी या विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुरोध पर इन अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षित व्यवस्था भी करेगी।
- (8) आवास इकाई ऐसे प्रत्येक समय परिसर में एक पर्यवेक्षक / प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, जब कोई पेट्रॉन प्रतिष्ठान का उपयोग कर रहा हो या यह जन सामान्य के लिए खुला हो।
- (9) आवास इकाई परिसर का निरीक्षण करने या तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत पदधारी या विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अबाधित पहुंच प्रदान करेगी।
- 6. आवास इकाइयों के लिए सुझावात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत—आवास इकाई को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा—
 - (क) किसी पेट्रॉन/उनके अतिथि/आगंतुक, जिनके विरूद्ध किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने का उचित संदेह विद्यमान हो, की पहचान करने और विवरण की रिपोर्ट करने के लिए प्रणाली विकसित करना,
 - (ख) यह सत्यापित करने के लिए समय निकालना कि चेक-इन के समय फोटो पहचान-पत्र वास्तव में संबंधित व्यक्ति का है। बड़े आकार की टोपी, चेहरे ढ़कने वाला मास्क तथा धूप चश्में का सावधानी पूर्वक अनुश्रवण किया जायेगा,
 - (ग) फ्रांट डेस्क पर आपातकालीन संपर्क संख्या यथा महिला हेल्प लाइन संख्या, पुलिस आयुक्त / विरष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जिला मिजस्ट्रेट / निकटतम पुलिस थाना / 112 के संपर्क नंबर की सूची प्रदर्शित करना,
 - (घ) प्रतिष्ठान के फ्रंट डेस्क पर मानव तस्करी के विरूद्ध सरकार के मार्गदर्शी सिद्धातों की प्रति प्रदर्शित करना,
 - (ड़) पेट्रॉन को उपलब्ध कराये जाने वाले परिसर और प्रसाधन सामग्री को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाये रखना,
 - (च) परिसर में उचित अग्नि शमन और सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करना,
 - (छ) पहुंच योग्य सड़क पर आवास इकाई स्थापित करना।
- 7. तलाशी और निरीक्षण करने की शक्तियाँ—(1) यदि प्राधिकृत पदधारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई आवास इकाई इस विनियमावली में निर्धारित अनिवार्य औपचारिकताओं का अनुपालन नहीं कर रही है तो ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् प्राधिकृत पदधारी या विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्ति होगी—
 - (क) आवास इकाई के परिसर में सदैव प्रवेश करना और तलाशी करना,
 - (ख) उक्त भवन में तलाशी के परिणाम-स्वरूप पाये गये किसी अभिलेख या वस्तु को अभिग्रहीत करना, जो इस विनियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग हेतु आशयित हों, या उपयोग किए जाने हेतु युक्ति-युक्त रूप से संदिग्ध हों,
- (2) इस धारा के अधीन समस्त तलाशी और बरामदगी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

- 8. इस विनियमावली और उसकी प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए शस्ति—(1) यदि विहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवास इकाई इस विनियमावली की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रही है तो वह ऐसी आवास इकाई को कारण बताओ उसकी प्रक्रिया के नोटिस जारी करेगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
- (2) आवास इकाइयों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण / तर्कों की संवीक्षा करने के पश्चात्, यदि विहित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवास इकाई ने विनियम में उल्लिखित अनिवार्य औपचारिकताओं का जानबूझकर उल्लंघन किया है तो उसे ऐसे निष्कर्ष निकालने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक तर्कपूर्ण स्पष्ट आदेश पारित करना होगा और सराय अधिनियम 1867 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1867) की धारा 14 में उल्लिखित आर्थिक शास्ति उदग्रहीत करना होगा।
- (3) यदि वहीं आवास इकाई, तीसरी बार जानबूझकर इस विनियमावली में निर्धारित अनिवार्य औपचारिकताओं का जानबूझकर उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो विहित प्राधिकारी ऐसी इकाई के रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को किसी निर्दिष्ट अविध के लिए प्रतिसंहत करने का विनिश्चय कर सकता है। विहित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा कि ऐसी आवास इकाई उस अविध के दौरान संचालित नहीं होगी, जब उसका रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिसंहत कर दिया गया हो।
- (4) विहित प्राधिकारी को ऐसे समस्त पारित आदेशों की एक प्रति संबंधित क्षेत्र के मंडलायुक्त को अवश्य प्रेषित करना होगा।
- (5) आवास इकाई, विहित प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे समस्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकती है, और अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकारी पुनरीक्षण याचिका प्राप्त किये जाने के दिनांक से 45 दिनों की अविध के भीतर आदेश पारित करेगा या अंतिम विनिश्चय को विस्तारित करने का लिखित रूप में कारण अभिलिखित करेगा।
- 9. दो स्तरीय समितियों द्वारा पर्यवेक्षण—(1) अधिनियम तथा इस विनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के नियमित पर्यवेक्षण एवं समीक्षा तथा उनसे संबंधित मामलों के निस्तारण एवं प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित द्विस्तरीय समितियाँ गठित की जायेंगी—
 - (क) जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति
 - (ख) राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति
- (2) प्रत्येक त्रैमास में इस विनियमावली के अधीन कृत कार्रवाई, जिसमें रजिस्ट्रीकरण आवेदन और अनिवार्य औपचारिकताओं का अनुपालन न किये जाने सम्बन्धित मामलें सम्मिलित हैं, की जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा अनिवार्य रूप से समीक्षा की जायेगी।
- (3) जिला स्तरीय समिति, समय-समय पर इस विनियमावली के अधीन कार्य करने के संबंध में न ऑनलाइन पोर्टल की समुचित कार्य प्रणाली की समीक्षा करेगी और इसकी समुचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
 - (4) उक्त जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा-
 - (क) जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष
 - (ख) जिला पुलिस प्रभारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक और उन जिलों में, जहां पुलिस किमश्नरेट प्रणाली लागू हो, यथास्थिति अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) या संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) उपाध्यक्ष
 - (ग) अपर जिला मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव
 - (घ) संयुक्त निदेशक, अभियोजन सदस्य

- (ड) उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का पर्यटन अधिकारी सदस्य
- (च) विकास प्राधिकरण सहित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या सचिव सदस्य
- (छ) अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य, जिनका सहयोग और उपस्थिति अध्यक्ष समीचीन समझे।
- (5) राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का अर्धवार्षिक पर्यवेक्षण करेगी तथा आवास इकाई के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के संबंध में नीति बनायेगी तथा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगी।
- (6) राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अस्वीकृत आवेदनों की सूची के साथ-साथ मंडलायुक्त द्वारा संकलित आवास इकाइयों की उल्लंघन सूची की समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हो तो कोई नीति स्तरीय स्पष्टीकरण जारी करेगी।
- (7) राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति आवास इकाइयों के लिए रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए समय-सीमा की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित कर सकती है कि विहित प्राधिकरण आवासीय इकाइयों को रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए समीचीन रीति से समस्त आवश्यक कार्रवाई करें।
 - (8) राज्य स्तर पर उचित कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा—
 - (क) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, गृह अध्यक्ष
 - (ख) प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग उपाध्यक्ष
 - (ग) पुलिस महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती सदस्य
 - (घ) जीएसटी / बिक्री कर व्यापार कर विभाग का अधिकारी सदस्य
 - (ड) अन्य विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य जिनका सहयोग और उपस्थिति अध्यक्ष समीचीन समझे।
- 10. सद्धावनापूर्वक कृत कार्रवाई का संरक्षण—अधिनियम या इस विनियमावली के अनुसरण में सद्धावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

आज्ञा सें, संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव।

GRIH (POLICE) DEPARTMENT

Anubhag-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 2839/6-p-9-2023, dated 28 June, 2023.

NOTIFICATION

June 28, 2023

No. 2839/6-p-9-2023—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Sarai Act, 1867 (Act No. 22 of 1867) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following Regulations with a view to provide for a speedy and transparent procedure to regulate the operation of accommodation units:

Uttar Pradesh Hotel and Other Supplementary Accommodation (Control) Regulations, 2023

- **1. Short title and commencement**—(1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Hotel and Other Supplementary Accommodation (Control) Regulations, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.
- (3) These Regulations shall be read in consonance with all prevailing statutes and the Regulations thereof.
 - 2. Definitions—(1) In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context—
 - (a) "accommodation unit" means such establishments including the premises thereof, which are used for shelter and accommodation of travellers and includes all hotels, resorts, guest houses, farm stays and all other such accommodation units which are used by travellers for shelter, but does not include Government guest houses;
 - (b) "Act" means the Sarai Act, 1867 (Act no. 22 of 1867);
 - (c) "appellate authority" means the Divisional Commissioner of the respective area;
 - (d) "authorized official" means the District Magistrate of concerned area or any Gazetted Officer authorized for the purposes of these Regulations by the State Government;
 - (e) "employee" means a person who renders any service in connection with the operation of accommodation unit and is on the payroll of such accommodation unit. It does not include a person who is exclusively on the premises for repair or maintenance of the promise, delivery of goods to the premise or other similar relationships;
 - (f) "local management" means a person who is duly appointed by the owner of an accommodation unit to oversee the functioning at the premises of such establishment;
 - (g) "patron" means an individual or customer who receives a stay or lodging facility at an accommodation unit;
 - (h) "prescribed authority" means the District Magistrate of the concerned area.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Sarai Act, 1867 (Act no. 22 of 1867) shall have the same meanings respectively assigned to them the said Act.
- **3. Development of Online Portal**—(1) An online web and mobile application based portal shall be developed, by the State Government, for registration of accommodation unit .
 - (2) The abovementioned portal shall be integrated with the Nivesh Mitra portal.
- (3) After development of such portal, the State Government shall publish a notification containing the description of portal and instructions for its usage.
- **4. Mandatory Registration to operate an Accommodation units**–(1) After a lapse of thirty (30) days from issuance of notification regarding development of online portal, no Accommodation Unit shall operate without obtaining the registration certificate. District Magistrate shall be empowered to take all necessary legal actions to ensure the same.
- (2) At the time of application for registration, an undertaking on affidavit shall be submitted by the applicant mentioning that he/she shall comply with the provision of Act and these Regulations made thereunder.

- (3) Within 45 days from date of application (for registration) on portal, the prescribed authority shall either register such unit and issue the registration certificate or reject the application mentioning the specific reasons of rejection. Failure to decide on the application within this period of 45 days shall be construed as deemed registration and the registration certificate shall be issued automatically on the portal.
- (4) The person aggrieved by the rejection of the said application may file a revision before the appellate authority. The decision of the appellate authority shall be final.
- (5) For every rejected application, the prescribed authority must submit the reasons of rejection to the Divisional Commissioner in writing.
- **5. Mandatory Compliances for Accommodation units**—(1) The Accommodation unit shall display the registration certificate issued by the prescribed authority at the main entrance of the establishment.
- (2) The Accommodation unit shall not allow any patron under any circumstances to avail the lodging facility without obtaining and entering into records following details at the front desk:
 - (a) a photocopy of valid Government issued photo ID card;
 - (b) name, age and address of the patron;
 - (c) an undertaking from the guest that he/she has not brought any hazardous substance or any illegal weapon to the premises.
- (3) The Accommodation unit shall not allow any visitor or guest of patron to access the stay rooms / lodging facility area without obtaining and entering into records following details at the front desk:
 - (a) a photocopy of valid Government issued photo ID card of the guest/visitor;
 - (b) name, age and address of the guest/visitor along with the name of concerned patron;
 - (c) time of arrival and departure.
- (4) The Accommodation unit shall not employ anyone without applying for his/her police verification certificate.
- (5) The Accommodation unit shall install CCTV cameras at entry/exit points, front desk and in parking areas and shall maintain the CCTV footage for at-least 30 days.
 - (6) The Accommodation unit shall maintain records of following for a period of 2 years:
 - (a) details of all the patrons (their names, age, government issued photo identity card/certificate number and address along with the check in-check out date).
 - (b) details of all the employees (their names, age, government issued photo identity card/certificate number and address).
- (7) The Accommodation unit shall also make requisite arrangements to produce these records upon request of Authorized official or any other official duly authorized by prescribed Authority for this purpose at the time of inspection or otherwise.
- (8) The Accommodation unit shall ensure the presence of a supervisor /manager on the premises at all such times when any patron is using the establishment or it is open for public.
- (9) The Accommodation unit shall provide unhindered access to the Authorized official or any other official duly authorized by prescribed Authority to carry out inspection or search the premises.

- **6. Suggestive Guidelines for Accommodation units**—The accommodation unit shall endeavor to ensure the following:—
 - (a) develop a system to identify and report details of any patron/their guest/visitor against whom a reasonable suspicion of being involved in any criminal activity exists;
 - (b) take the time to verify that the photo ID at check-in is actually that of the concerned person. Oversized hats, face masks and sunglasses shall be monitored cautiously;
 - (c) display a list of emergency contact number e.g. women help line number, contact number of Police Commissioner/SSP/DM/Nearest Police Station/112 at the front desk;
 - (d) display a copy of the Government guidelines against human trafficking at front desk of establishment:
 - (e) maintain the premises and toiletries offered to patron clean and hygienic;
 - (f) ensure proper fire and safety precautions in the premises;
 - (g) establish the accommodation unit at an approachable road.
- **7. Powers to Search and inspect**—(1) If the Authorized official has a reason to believe that the accommodation unit is not complying with the mandatory compliances stipulated in these Regulations, then after recording the reasons of such belief in writing, the Authorized official or any officer duly authorized by Prescribed Authority shall have the power to:
 - (a) enter and search the premises of accommodation unit at all times.
 - (b) to seize any record or article found as a result of the search in the said building, which are intended to be used, or reasonably suspected to have been used, in contravention of the provisions of these Regulations.
- (2) All searches and seizures under this section shall be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974).
- **8.** Penalty for contravention of these Regulations and procedure thereof—(1) If it appears to the Prescribed Authority that an accommodation unit has failed to comply with the mandatory requirements of these Regulations, it shall issue a show cause notice to such accommodation unit and shall provide an opportunity to be heard.
- (2) After scrutinizing the clarifications/arguments put forth by the accommodation units, if the Prescribed Authority concludes that the Accommodation unit has deliberately violated mandatory compliances mentioned in the rule, it must pass a reasoned speaking order mentioning the reasons to conclude so and levy a pecuniary penalty as mentioned in section 14 of the Sarai Act 1867 (Act no. 22 of 1867).
- (3) If the same accommodation unit is found to be deliberately contravening the mandatory compliances stipulated in these Regulations for the third time, the Prescribed Authority may decide to revoke the registration certification of such unit for a specified period of time. Prescribed authority will be empowered to take all necessary legal actions to ensure that such accommodation unit does not operate during the period its registration certificate is revoked.

- (4) Prescribed authority must send a copy of all such orders passed to the Divisional Commissioner of the concerned area.
- (5) The Accommodation unit may file a revision petition before the Appellate Authority against all such orders passed by the prescribed authority, and the decision of Appellate authority shall be final. The Appellate authority shall pass the order within a period of 45 days from the date of receipt of the revision petition, or state reasons, in writing, for an extension on the final decision.
- **9. Supervision by two-tier Committees**—(1) The following two-tier Committees shall be constituted in relation to the regular supervision and review of any proceedings under the Act and these Regulations and the disposal and management of their related matters:
 - (a) District Level Supervision Committee
 - (b) State Level Supervision Committee
- (2) Every quarter, the action taken under these Regulations, including the application of registration and the cases regarding non-compliances of mandatory requirements shall be compulsorily reviewed by the District Level Supervision Committee.
- (3) The District Level Supervision Committee shall, from time to time, review the appropriate functioning of the online portal with respect to carrying out the functions under these Regulations and take necessary actions to ensure its proper functioning.
 - (4) The District Level Supervision Committee will be constituted as under:-
 - (a) District Magistrate Chairman
 - (b) District Police In-charge, Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police and in districts where the Police Commissionerate system is in force the Additional Commissioner of Police (Law and Order) or Joint Commissioner of Police (Law and Order), as the case may be -Vice Chairman.
 - (c) Additional District Magistrate Member Secretary
 - (d) Joint Director Prosecution Member
 - (e) Tourism Officer of the Department of U.P. Tourism Member
 - (f) Vice President or Secretary of Authorities including Development Authority Member
 - (g) Other special invitees whose cooperation and presence the Chairman deems expedient.
- (5) The State Level Supervision Committee shall supervise the District Level Supervision Committee half-yearly and make policy and issue guidelines regarding the effective supervision and control of accommodation unit.
- (6) The State Level Supervision Committee shall review the list of rejected applications for obtaining registration certificates as well as list of violations by accommodation units as compiled by the Divisional Commissioner and issue any policy level clarifications if found necessary.

- (7) The State Level Supervision Committee shall monitor the timelines for accommodation units to obtain registration certificate and may ensure that the Prescribed Authority take all necessary actions to provide registration certificates to accommodation units in an expedient manner.
- (8) The State Level Supervision Committee will be constituted at the State Level to take appropriate action as follows:-
 - (a) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home Chairman
 - (b) Principal Secretary, Tourism Department Vice Chairman
 - (c) Director General of Police or his nominee Member
 - (d) Officer of GST/ Sales Tax Business Tax Department Member
 - (e) Other specially invited members whose co-operation and presence the Chairman may deems expedient.
- 10. Protection of action taken in good faith—No suit, prosecution or legal proceeding shall lie against the Government or any person authorized by the Government in respect of anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of the Act or these Regulations.

By order, SANJAY PRASAD, Principal Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग

अनुभाग—9 अधिसूचना (शक्ति) 28 जून, 2023 ई0

सं0 3117 / छ:-पु0-9-23-20(10)(16) / 88 T.C.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित समसेमेस्टर परीक्षा / वार्षिक परीक्षा / विशेष बैक पेपर परीक्षा, जून-2023 के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-17 सन 1962) की धारा-2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है, दिनांक 28 जून, 2023 से दिनांक 20 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बंधित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी समस्त शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से, डा० बी० डी० पॉल्सन, सचिव।

GRIH (POLICE) DEPARTMENT

Anubhag-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3117/VI-P-9-23-20(10)(16)/88 T.C. Dated 28 June, 2023

NOTIFICATION

(POWERS)

June 28, 2023

No. 3117 /VI-P-9-23-20(10)(16)/88 T.C.—In exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from June 28, 2023 till July 20, 2023 all the Superintendents of the centres of Even Semester/Annual Examination/Special Back Paper Examination June-2023 conducted by Board of Technical Education, Uttar Pradesh as defined in clause (n) of Section 2 of Uttar Pradesh Technical Education Act, 1962 (U.P. Act No. XVII of 1962) as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said code on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By Order, Dr. B. D. Paulson, Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग

अनुभाग-9 अधिसूचना (शक्ति) 31 जुलाई, 2023 ई0

सं0 3478 / छः-पु0-9-23-20(10)(16) / 88 टीसी—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा UPJEE(P)-2023 के समस्त केन्द्र पर्यवेक्षकों को जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-17 सन 1962) की धारा-2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है, दिनांक 02 अगस्त, 2023 से दिनांक 06 अगस्त, 2023 (दिनांक 07 अगस्त, 2023 आरिक्षत दिवस) तक की अवधि के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हे सम्बंधित केन्द्रों, जिनके वे पर्यवेक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी समस्त शक्तियाँ प्रद्वन करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

डा० बी०डी० पॉल्सन, सचिव।

GRIH (POLICE) DEPARTMENT

Anubhag-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3478 /VI-P-9-23-20(10)(16)/88 T.C. Dated 31 July, 2023

NOTIFICATION (POWERS)

July 31, 2023

No. 3478 /VI-P-9-23-20(10)(16)/88 T.C.—In exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from August 02, 2023 till August 06, 2023 (August 07, 2023 Reserve day) all the Supervisors of the centres of UPJEE(P)-2023 conducted by Joint Entrance Examination Council, Uttar Pradesh, Lucknow as defined in clause (n) of Section 2 of Uttar Pradesh Technical Education Act, 1962 (U.P. Act No. XVII of 1962) as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said code on such Executive Magistrate, to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By Order, Dr. B. D. Paulson, Secretary.

सूचना विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

02 जनवरी, 2023 ई0

सं0 01/उन्नीस-1-2023-32/2003 टी०सी०-I—श्री यशोवर्धन तिवारी, उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पद, वेतनमान रु० 15,600 से 39,100 (ग्रेड वेतन रु० 7,600) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12, पर पदोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

- 2— श्री यशोवर्धन तिवारी को संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अविध में रखा जाता है।
 - 3— यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।

सं0 02/उन्नीस-1-2023-32/2003 टी०सी०-I—श्री जहांगीर अहमद, उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पद, वेतनमान रु० 15,600 से 39,100 (ग्रेड वेतन रु० 7,600) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12, पर पदोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

- 2— श्री जहांगीर अहमद को संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अविध में रखा जाता है।
 - 3— यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।

02 फरवरी, 2023 ई0

सं0 104/उन्नीस-1-2023-32/2003, टी०सी०-I—श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, फोटो अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को फिल्म निर्माण अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पद पर वेतन रु० 15,600-39,100 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 ग्रेड वेतन रु० 5,400 में उपलब्ध वास्तविक रिक्ति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

- 2— श्री दिनेश कुमार पाण्डेय को फिल्म निर्माण अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अविध में रखा जाता है।
 - 3- यह आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगा।

13 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 712/उन्नीस-1-2023—सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारियों को सहायक निदेशक (वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु० 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2— निम्नांकित जिला सूचना अधिकारी / सूचना अधिकारियों को प्रोन्नित के पद पर योगदान देने की तिथि से ही सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति का पद
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1	प्रशांत कुमार श्रीवास्तव	सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक
2	चन्द्र मोहन	सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक
3	प्रभात श्रीवास्तव	सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक
4	जितेन्द्र प्रताप सिंह	सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक
5	इन्द्रमणि पाण्डेय	जिला सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक
6	डा० सीमा गुप्ता	सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक
7	सुनील कुमार कन्नौजिया	सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक

सं0 713 / उन्नीस-1-2023—श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पद (वेतनमान रु० 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन रु० 7,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12) पर पदोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक को प्रोन्नित के पद पर योगदान देने की तिथि से ही संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नित माना जायेगा।

> आज्ञा से, संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2) समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना (अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

08 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 458/आठ-वि०भू०अ०अ०(गीडा)गोरखपुर—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन औद्योगिक परियोजना हेतु जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवॉ, परगना भौवापार, ग्राम सहबाजगंज में कुल 0.3070 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-

(i) गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मैसर्स गैलेन्ट इस्पात को आवंटित भूमि में सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु आवंटित भूमि से नेशनल हाइवे से जोड़ने हेतु एवं सीमेन्ट प्लान्ट के पूरब पूर्व से संचालित एप्रोच रोड से जोड़ने हेतु प्रभावित भूमि के अधिग्रहण होने से 150 करोड़ की लागत से बनने वाली सीमेन्ट फैक्ट्री में प्रत्येक वर्ष लगभग 06 लाख टन सीमेन्ट का उत्पादन होगा।

- (ii) इस इकाई में नये निवेश के बाद 700 व्यक्तियों के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होगें।
- (iii) इस फैक्ट्री को गोरखपुर में स्थापित हो जाने के बाद गोरखपुर-बस्ती मण्डल तथा बिहार के क्षेत्रों में, जहाँ वर्तमान समय में सीमेन्ट बाहर से मंगायें जाते है, बाजार में बदलाव होगा।

उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रस्तावित सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना को रेखांकित करते हुए अनेक सम्भावित लाभों को रेखांकित किया गया है, जिसमें एक प्रमुख लाभ यह है—परिचालन लागत में कमी, राजस्व वृद्धि, कम पूँजी लागत, ग्राहकों को संतुष्टि एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा, परियोजना द्वारा गाँव का विकास होगा, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगीं, व्यापार के स्रोत में वृद्धि हो जायेगीं तथा रोजगार के नये अवसर में वृद्धि होगीं।

4-भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है—

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा-सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोरखपुर	सहजनवॉ	भौवापार	सहबाजगंज	433	0.0240
				434	0.0920
				435	0.0830
				496 मि0	0.0800
				432	0.0280
				योग	0.3070

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमे अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उढाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कृष्णा करुणेश, जिलाधिकारी, गोरखपुर।

INDUSTRIAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

December 08, 2023

No. 458/VIII-S.L.A.O.-(GIDA) Gorakhpur–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of appropriate government) is of the opinion that Gorakhpur Industrial Development Authority Gorakhpur (requiring body name) for Industrial Development Project in District-Gorakhpur, Tehsil-Sahjanwa, Pargana-Bhowapar, Village-Sahbajganj in area 0.3070 hectares of land is required, for the Industrial Development namely, Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA).

- 2. The Social Solution Assessment Study has been done by the State Social Solution Assessment Agency and its recommendations have been submitted to the appropriate government which has been approved by the appropriate government on January 27, 2023 has been approved.
 - 3. The summary of the Social Solutions Assessment Report is as follows-
- (i) Acquisition of the affected land through the Gorakhpur Industrial Development Authority, Gorakhpur, to connect the land allotted to M/s. Gallant Ispat for the establishment of a cement plant in the land allotted for public purpose to the National Highway and to connect the cement plant with the approach road operating from the east. About 06 lakh tonnes of cement will be produced every year in the cement factory to be built at a cost of Rs. 150 crore.
- (ii) After the new investment in this unit, new employment opportunities will be created for 700 persons.
- (iii) After this factory is established in Gorakhpur, there will be a change in the market in Gorakhpur-Basti Mandal and areas of Bihar, where at present cement is imported from outside.

In addition to the above mentioned benefits, several possible benefits have been outlined underlining the establishment of the proposed cement factory, in which one of the major benefits is reduction in operational cost, revenue growth, low capital cost, customer satisfaction and promotion of economic development. The village will develop through the project, transport facilities will increase, sources of business will increase and new employment opportunities will increase.

- 4. Total zero families are likely to be displaced due to land acquisition.
- 5. The Governor is, therefore, pleased to notify for general information the following lands in the following schedule for public purposes.

Schedule					
District	Tehsil	Pargana	Village	Gata No.	Total Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Gorakhpur	Sahjanwa	Bhauvapar	Sahabajganj	433	0.0240
				434	0.0920
				435	0.0830
				496 m	0.0800
				432	0.0280
				Total	0.3070

- 6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
- 7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.
- 8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land for the purpose of acquisition may be inspected in the Office of the Collector, Gorakhpur.

KRISHNA KARUNESH, Collector, Gorakhpur.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-18 नियम-20 का उपनियम (2) समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना (अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत) 21 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 10100/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/वाई0ई0ए0/गौतमबुद्धनगर—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु समुचित सरकार/कलेक्टर

की राय है, कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से उक्त प्रयोजन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु राजस्व ग्राम दनकौर, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर की कुल 0.4719 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र-संख्या-9518/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/वाई०ई०ए०/गौतमबुद्धनगर दिनांक 26 सितम्बर, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-

जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु आवश्यक भूमि 0.4719 हे0 भूमि की (Absolute bare minimum) न्यूनतम आवश्यकता बतायी गयी है। इससे कम सीमा तक परियोजना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

4-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

5—उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्धनगर को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

6—अतः राज्यपाल उक्त प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है—

			अनुसूची		
जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड-सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	दनकौर	2	0.0506
				5	0.4213
				योग	0.4719

^{7—}अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमे अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते है।

^{8—}अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपित्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमे अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बलराम सिंह, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR [UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT, 2013] NOTIFICATION

December 21, 2023

No. 10100/VIII-ADM(LA)/YEA/Gautambudh Nagar—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Appropriate Government/Collector is satisfied that a total of 0.4719 hectare land is required in the Revenue Village-Dankaur, Tehsil-Sadar, District-Gautambudh Nagar for the purpose namely "planed development of YEIDA" through the Yamuna Expressway Industrial Development Authority.

- 2. Social Impact Assessment study was carried out by Gautam Buddha University District Gautmbudh Nagar as Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to "the Appropriate Government which has approved the recommendations vide Letter No. 9518/VIII-ADM(LA)/YEA/Gautambudh Nagar Dated September 26, 2023.
 - 3. The summary of the Social Impact Assessment Report is as follow-

A total land area of 0.4719 hectare is required for "planed development of YEIDA" the technical committee based on land optimization has laid down 0.4719 hectare as minimum land requirement. There is no other alternative, less then this area, required by the acquiring body to complete the project. :

- 4. Due to land acquisition, no family is being displaced in the said village.
- 5. The Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka(8)/2014 dated August 06, 2014 has provided that the Assistant Collector or Deputy Collector as the case may be, of the concerned Tehsil shall be appointed "Administrator for Rehabilitation and Resettlement" of the affected families within the respective territorial Jurisdictions thereof. According to the said Govt. Order, the Deputy Collector Sadar, District Gautambudh Nagar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families within the respective territorial jurisdiction.
- 6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that land mentioned in the schedule given below is needed for this purpose.

SCHEDULE								
District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired			
1	2	3	4	5	6			
					Hectares			
G. B. Nagar	Sadar	Dankaur	Dankaur	2	0.0506			
				5	0.4213			
				Total	0.4719			

- 7. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the subsoil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
- 8. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.
- 9. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

BALRAM SINGH, Collector, Gautambudh Nagar.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1) समुचित सरकार / जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा (अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

02 फरवरी. 2024 ई0

सं० ७०३—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-१६, चन्दौसी (अपेक्षित निकाय
का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला
सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम मढ़न, बुकनाला व डोंडी में स्थिति ०.४३५२ हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की
उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या दिनांक दिनांक को निर्गत की
गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट
कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक
नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम मढ़न, बुकनाला व डोंडी में स्थिति 0.4352 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है—

अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	मढ़न	677	0.0960
				758	0.1056
				योग—	0.2016
			बुकनाला		0.0016
			डोंडी	393	0.0600
				548	0.0960
				553	0.0760
				योग—	0.2320
				कुल योग—	0.4352

अनुसूची-ख (विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड-सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
					(हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

-विस्थापित परिवारो की संख्या ''शून्य''-

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मनीष बंसल, जिलाधिकारी, जनपद सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR [UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT] NOTIFICATION

February 02, 2024

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, The Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose and the land to the extent of 0.4352 hectares in Village-Madhan & Dondi Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal, as given schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Sambhal to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

District	District Tehsil		Village	Plot No.	area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Madhan	677	0.0960
				758	0.01056
				Total	0.2016

222	उत्तर प्रदेश गजट,	, 02 मार्च, 2024 ई	० (फाल्गुन १२, १९४५	शक संवत्)	[भाग 1-क
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	l Sambhal	Sambhal	Buknaala	710	0.0016
			Dondi	393	0.0600
				548	0.0960
				553	0.0760
				Total	0.2320

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilition
1	2	3	4	5	6

Hectares

Grand Total..

0.4352

No. of displaced families is 'Zero'

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Sambhal for the purpose of acquisition.

By order, Secretary/Authorised Officer.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR UNDER SUB SECTION(2) OF SECTION 19 OF THE ACT

By the order of declaration made under Government notification no.......... dated for 0.4352 hectare of land is recuired in the village-Madhan, Buknaala and Dondi, Pargana-Sambhal, District – Sambhal is recuired for public purpose, namely project Madhya Ganga Canal Phase-2 through Irrigation and Water Resouce department, Uttar Pradesh, through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div-16, Chandausi (Name of Acquiring body) and I hereby Published the declaration made therein and summary of Rehabiliation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabiliation and Resettlement scheme is given below –

.....

NOTE--The plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Sambhal for the purpose of Acquisition.

By Order,
MANISH BANSAL,
Collector.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1) समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा (अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

08 फरवरी, 2024 ई0

सं० 718—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम असमौली, इकरोटिया, मदाला फतेहपुर, मवई डोल, शाहपुर सिरपुडा, हाजिरपुर उर्फ हैदरपुर, सतू पुरा, नन्दपुर वीटा व दुल्हापुरबन्द उर्फ दारापुर में कुल 1.3872 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचनो संख्या-90/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर सम्भल को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम असमौली, इकरोटिया, मदाला फतेहपुर, मवई डोल, शाहपुर सिरपुडा, हाजिरपुर उर्फ हैदरपुर, सतू पुरा, नन्दपुर वीटा व दुल्हापुरबन्द उर्फ दारापुर में कुल 0.00 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु सम्भल कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है—

अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भिम)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड-सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	असमौली	657	0.0150
				658	0.0010
				711	0.1450
				712	0.0680
				875	0.0305
				862	0.0560
				863	0.0440
				864	0.0048
				योग—	0.3643

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	इकरोटिया	366	0.0335
			मदाला फतेहपुर	594	0.0640
				1068	0.2560
				1256	0.0200
				योग—	0.3400
			मवई डोल,	348	0.0060
				352	0.0175
				336	0.0110
				716	0.0990
				676	0.0522
				योग—	0.1857
			शाहपुर सिरपुडा	426	0.0100
			हाजिरपुर उर्फ हैदरपुर	246	0.1476
				योग—	0.1476
			सेतू पुरा	93	0.1557
				94	0.0666
				योग—	0.2223
			नन्दपुर वीटा	505	0.0494
			दुल्हापुरबन्द उर्फ दारापुर	380मि0	0.0344
				योग—	0.0344
				कुल योग-	1.3872

अनुसूची-ख (विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	मू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिहिन्त क्षेत्रफल
					(हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

–विस्थापित परिवारो की संख्या ''शून्य''–

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मनीष बंसल, जिलाधिकारी,

जनपद सम्भल।

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

February 08, 2024

No. 718—Whereas preliminary notification no. 90 / आত-বিতম্ত্রতা / দুরাবাব dated September 18, 2023 was issued under sub section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilition and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.3872 hectares of land is required in the Village-Asmoli, Ekrotiya, Madala Fathepur, Mawai Dol, Shahpur Sirpura, Hazirpur *Urf* Hedarpur, Satupura, Nandpur Vita and Dulahapurband *Urf* Darapur, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for the public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (Name of Acquiring body) and lastly published on dated September 30, 2023. The Deputy Collector Sambhal was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose and the land to the extent of 1.3872 hectares in Village-Asmoli, Ekrotiya, Madala Fathepur, Mawai Dol, Shahpur Sirpura, Hazirpur *Urf* Hedarpur, Satupura, Nandpur Vita and Dulahapurband *Urf* Darapur, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal as given schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Asmoli	657	0.0150
				658	0.0010
				711	0.1450
				712	0.0680
				875	0.0305
				862	0.0560
				863	0.0440
				864	0.0048
				Total	0.3643

	\			(r	,				
उत्तर	परंश	गत्तट	02	मार्च	2024	ਵੰ∩	(फाल्ग्नन	12	19/15	91त	स्तत)
0111	77 71	i vi c,	UZ	· 11 ~1,	2027	ŲŪ	(1/1/	14,	1070	117/	(17(1)

भाग 1-क

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Ekrotiya	366	0.0335
			Madala Fathepur	594	0.0640
				1068	0.2560
				1256	0.0200
				Total	0.3400
			Mawai Dol	348	0.0060
				352	0.0175
				336	0.0110
				716	0.0990
				676	0.0522
				Total	0.1857
			Shahpur Sirpura	426	0.0100
			Hazirpur Urf Hedarpur	246	0.1476
				Total	0.1476
			Satupura	93	0.1557
				94	0.0666
				Total	0.2223
			Nandpur Vita	505	0.0494
			Dulahapurband Urf Darapur	380मि0	0.0344
				- Grand Total	1.3872

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectares

No. of displaced families 'Zero'

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order, Secretary/Authorised Officer.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR UNDER SUB SEDTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10 Bulandshahr By the order of the declaration made under Government notification No								
								of Rehabiliation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabiliation
								and Resettlement scheme is given below –
								NOTEThe plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Sambhal for the purpose of acquisition.
By Order, MANISH BANSAL, Collector.								
जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश								
प्रारूप-18								
नियम-20 का उपनियम (2)								
(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)								
16 नवम्बर, 2023 ई0								
सं0 333—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम								
2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार / कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय								
है, कि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड-2, हरिद्वार (आपेक्षक निकाय								
का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद सम्भल,								
तहसील व परगना सम्भल, ग्राम परियावली में कुल 0.1408 हे0 भूमि की आवश्यकता है।								
2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा								
समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक को								
अनुमोदित किया गया है।								
3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है— रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह								
प्रस्ताव सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है—								

अपरिहाय	٠,				कुल	शून्य	परिवार	के	विस्थापित	होने	की	संभावना	ਲੈ	इस	विस्थापन	के	लिए
,								व	गे प्रभावित	परि	वारों	के पुनव	र्गसन	एव	पुनर्व्यवस	थापन	ा के
उद्देश्य	स प्रशा	सक निर	युक्त	किया	जाता	ह।											

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है—

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड-सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	परियावली	631	0.0960
				627	0.0448
				योग	0.1408

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपित्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मनीष बंसल, जिलाधिकारी, जनपद सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

November 16, 2023

No. 333-Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.1408 hectares of land is required in the

Village-Paryawali, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambal, District-Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal quality control divisin-2] Haridwar (name of requiring body).

- 2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated
 - 3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under—

Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

Schedules							
District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired		
1	2	3	4	5	6		
					Hectares		
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Paryawali	627	0.0448		
				631	0.0960		
				Total	0.1408		

- 6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
- 7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.
- 8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

MANISH BANSAL, *Collector*, *Sambhal*.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां कार्यालय, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

13 फरवरी, 2024 ई0 अधिसूचना

सं0 9001(1)/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/अधि0सू0/2023-24—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) की राय है कि राप्ती नहर, निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़ मुख्यालय बढ़नी सिद्धार्थनगर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, सरयू परियोजना के अन्तर्गत निकलने वाली इटवा शाखा के किमी0 18.300 से किमी0 19.400 के मध्य के गैप की भूमि को पूर्ण करने हेतु ग्राम-सेमरी, तप्पा-हीर, परगना-बाँसी पश्चिम, तहसील-इटवा के कुल क्षेत्रफल 1.664413 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—सरयू नहर परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्लीयरेयन्स के संबंध में पत्र दिनांक 19 जून, 2000 प्रस्तुत किया गया है। धारा-6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि अर्जन का प्रस्ताव है।

- 3—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है ।
- 4—अतः महामिहम राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्निलिखित अनुसूची में अंकित गाटावार / क्षेत्रफल भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमित देती हैं—

अनुसूची अर्जित किये जाने जनपद तहसील भू-खण्ड सं0 परगना ग्राम वाला क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर सिद्धार्थनगर बाँसी पश्चिम सेमरी इटवा 25/10.00027 25/231 0.00149 32 0.00542 0.00068 917 0.00352 921 0.00108 36 931 0.00230 1133 0.00108 0.00230 1134 1726 0.00609 0.00731 1137 0.00081 1163 1170 0.00027 1174 0.00027 0.00135 1258 1262 0.00230 1267 0.00095

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1292	0.00081
				1296	0.00108
				1297	0.00230
				1398मि0	0.00474
				1402	0.00108
				1489मि0	0.00718
				1730	0.00325
				1758	0.00393
				1763	0.00907
				1809	0.01788
				1889	0.00704
				1893	0.00081
				1894	0.00989
				1901	0.00176
				1906	0.00352
				1910	0.00311
				1915	0.00339
				1919	0.00284
				26	0.004
				27	0.003
				28	0.005
				29	0.001
				915	0.008
				37 / 01	0.044
				37 / 02	
				38 / 1	0.041
				38/2	
				39/1	0.022
				39/2	
				1075 / 1	0.038
				1076 / 1	0.036
				1135	0.010

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1136	0.010
				1164	0.005
				1263	0.012
				1264	0.013
				1266	0.003
				1172मि0	0.001
				1298	0.008
				1299	0.007
				1301	0.008
				1394	0.005
				1396	0.007
				1397	0.007
				1487मि0	0.002
				1488	0.020
				1491	0.044
				1723	0.002
				1724	0.004
				1725	0.013
				1768	0.025
				1769	0.027
				1807	0.023
				1808	0.004
				1890	0.074
				1891	0.136
				1892	0.006
				1896	0.020
				1897	0.020
				1898	0.021
				1899	0.008

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1904	0.027
				1905	0.013
				1913	0.023
				1914	0.008
				30	0.0015
				33	0.004
				40 / 1	0.001
				40/2	
				918	0.004
				926	0.0045
				1074 / 1	0.006
				1077 / 1	0.043
				1077 / 2	
				1130	0.004
				1169	0.0035
				1171	0.0015
				1302	0.0015
				1393	0.002
				1404मि0	0.0125
				1492	0.007
				1757	0.014
				1900	0.017
				1916	0.0065
				34	0.004
				961	0.002
				35	0.004
				919	0.006
				927	0.008
				928	0.008
				960	0.003

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1071	0.031
				1072	0.014
				1073	0.011
				1129	0.010
				1131	0.004
				1132	0.004
				1168	0.003
				1294	0.004
				1399	0.005
				1493	0.039
				1400	0.001
				1759	0.008
				1762	0.007
				1895	0.018
				1907	0.028
				1908	0.003
				923मि0	0.0010154
				1127मि0	0.00007777
				1128	0.00078206
				1172मि0	0.00007777
				933	0.008
				934	0.008
				951	0.005
				952	0.004
				1065	0.001
				1066	0.007
				1285	0.003
				1286	0.003
				1371	0.004
				1372	0.004

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1754	0.009
				1755	0.007
				1772	0.007
				1773	0.007
				1838	0.003
				1839	0.026
				940	0.00449
				947	0.00050
				1070	0.00018
				1159	0.00055
				1255	0.00014
				1280	0.00087
				1289	0.00028
				1290	0.00018
				1364	0.00014
				1405	0.00364
				1751	0.00494
				1778	0.00009
				1819	0.00009
				1846	0.00748
				1922	0.00307
				1270	0.012
				1283	0.008
				1369	0.015
				1753	0.024
				1770	0.014
				1813	0.008
				1841	0.048
				944	0.00501
				945	0.00334
				957	0.00601
				958 / 1	0.00818
				958/2	
				959	0.00200

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1161	0.00134
				1162	0.00134
				1281	0.00317
				1282	0.00267
				1291	0.00367
				1366	0.00300
				1403	0.00401
				1404मि0	0.00417
				1745	0.00551
				1746	0.00417
				1781	0.00591
				1782	0.00017
				1815	0.00067
				1816	0.00083
				1842	0.01137
				1843	0.01218
				1367	0.00618
				1165मि0	0.0005
				1490	0.00375
				योग	1.664413

5—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए महामहिम राज्यपाल/कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

6—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के प्रति लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पी०एस०यू०पी०—49 हिन्दी गजट—भाग 1 क—2024 ई०। मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1055/मा0शि0प0/परिषद्-9—सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्याः 262/पन्द्रह-7-2024 दिनांकः 27 फरवरी, 2024 द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय बारह के विनियम 17(7) एवं अध्याय चौदह के विनियम-2 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा 16(2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है।

अध्याय—चौदह विनियम—2	
वर्तमान विनियम	नवीन संशोधित विनियम
विनियम—2 निम्नलिखित परीक्षाएं इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है। क्रम 1 से लेकर 37 तक	क्रम 1 से लेकर 37 तक यथावत्। क्रम 38 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा संचालित सेकेण्डरी परीक्षा

अध्याय—बारह विनियम—17(7)	
वर्तमान विनियम	नवीन संशोधित विनियम
विनियम—17(7) निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।	क्रम 1 से लेकर 38 तक यथावत्। क्रम 39 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्डरी
क्रम 1 से लेकर 38 तक	परीक्षा

(दिब्य कान्त शुक्ल), सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
(भूमि अर्जन अनुभाग)
अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966)
की धारा-28 के अधीन
नोटिस

06 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1349 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (भूमि अर्जन अनुभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 की धारा—28 के अधीन नोटिस के माध्यम से वाराणसी नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु ''वैदिक सिटी सारनाथ भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, वाराणसी'' अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं:—

उत्तर—खसरा संख्या–543, 652, 710 ग्राम–सथवा, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी।

पूरब—खसरा संख्या—731, 733 ग्राम—सथवा, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—119, 138, 137, 144, 165, 167, 181 ग्राम—पतेरवा, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—1,2,3 व 4 ग्राम—मुगदरपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी।

दक्षिण—रिंग रोड जनपद—वाराणसी (30 भाग, 76 भाग, 75 भाग, 74 भाग, 73 भाग, 72 भाग, 71 भाग, 69 भाग, 66 भाग, 65 भाग, 62 भाग, 63 भाग, 200 भाग, 199 भाग, 198 भाग, 203 भाग, 212 भाग, 214 भाग, 222, 213 भाग, 216 भाग, 217 भाग ग्राम—सिंहपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—240 भाग, 246 भाग, 247 भाग, 248 भाग, 249 भाग, 225 भाग, 229 भाग, 224 भाग ग्राम—हसनपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—241 भाग, 240 भाग, 242 भाग, 243 भाग, 244 भाग, 246 भाग, 245 भाग, 290 भाग, 291 भाग, 288 भाग, 287 भाग, 286 भाग, 284 भाग, 282 भाग, 260 भाग, 261 भाग, 263 भाग, 264 भाग, 266 भाग, 267 भाग, 268 भाग, 269 भाग, 271 भाग ग्राम—सिंहपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी।)

पश्चिम—खसरा संख्या—224, 206, 205, 204, 202, 196, 194, 193, 192 ग्राम—गोइठहा, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी, खसरा संख्या—270 ग्राम—सिंहपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—178, 179, 180 ग्राम—हृदयपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—262 ग्राम—सिंहपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—242, 241 ग्राम—हृदयपुर, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी। खसरा संख्या—105, 524, 523, 522 ग्राम—सथवा, परगना—शिवपुर, तहसील—सदर, जिला—वाराणसी।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी—01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 से अपराहन 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम—1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपित्तयों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी—01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपित्त स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपित्त में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपित्तकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद, आवास आयुक्त।

NOTICE

Notice under section 28 of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965 (Uttar Pradesh Act No. 1, 1966) [Land Aqusition Section]

Date: 06 February, 2024

No. 1349/L.A.C./H.Q.—Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Land Acquisition Section) through a notice under Section 28 of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965, to solve the increasing housing problem of Varanasi City, "Vedic City Sarnath Bhoomi Vikas, Grihsthan Evam Bazar Yojana, Varanasi" has been notified. The limits of the area covered in the scheme are as follows:-

North-Khasra Number 543, 652, 710 Village-Sathwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

East–Khasra Number 731, 733 Village-Sathwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 119, 138, 137, 144, 165, 167, 181 Village-Paterwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 1, 2, 3 & 4 Village-Mugadarpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi.

South—Ring Road District Varanasi (30 part, 76 part, 75 part, 74 part, 73 part, 72 part, 71 part, 69 part, 66 part, 65 part, 62 part, 63 part, 200 part, 199 part, 198 part, 203 part, 212 part, 214 part, 222, 213 part, 216 part, 217 part Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra Number 240 Part, 246 Part, 247 Part, 248 Part, 249 Part, 225 Part, 229 Part, 224 Part, Village-Hasanpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 241 Part, 240 Part, 242 Part, 243 Part, 244 Part, 246 Part, 245 Part, 294 Part, 290 Part, 291 Part, 288 Part, 287 Part, 286 Part, 284 Part, 282 Part, 260 Part, 261 Part, 263 Part, 264 Part, 266 part, 267 part, 268 part, 269 part, 271 part Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.)

West-Khasra Number 224, 206, 205, 204, 202, 196, 194, 193, 192 Village-Goithaha, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi. Khasra Number 270 Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 178, 179, 180 Village-Hridaypur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi. Khasra Number 262 Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 242, 241 Village-Hridpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 105, 524, 523, 522 Village-Sathwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

The details of the Land, falling under the scheme and maps can be seen in the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division-Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owner will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of the Executive Engineer, Construction Division-Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objections shall be considered. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the Land/Building/Villages Name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

RANVIR PRASAD, *Housing Commissioner.*

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भूमि अर्जन अनुभाग) अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन नोटिस

15 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1381 / एल0ए०सी० / एच०क्यू०—उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-01 मोहनलालगंज, लखनऊ" बनाई है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं निम्न प्रकार है—

उत्तर—लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी रेलवे लाईन पर खसरा संख्या 3094 ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या 85 ग्राम पहाड़नगर टिकरिया, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या 477 व 476, ग्राम मोअज्जमनगर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या-315, 314/529, 296/528, ग्राम कबीरपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या-847, 845 भाग, 856, ग्राम कासिमपुर बिरुहा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या-493 व 523, ग्राम चाँद सराय, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पूरब—खसरा संख्या-325 भाग, 295 भाग, 298 भाग, 297 भाग, 299 भाग, 300 भाग, 320 भाग, 302 भाग, 292 भाग 303 भाग, 307 भाग, 306 भाग, 304 भाग, 289 भाग, 395 भाग, 396 भाग, 397 भाग, 408 भाग, 409 भाग, 410 भाग, 414 भाग, 416 भाग, 415 भाग, 509 भाग, 511 भाग, 512 भाग, 522 भाग, 521, 520 भाग, 527 भाग, 529 भाग, 534 भाग, 533 भाग, 537, 578 भाग, 581 भाग, 582 भाग, 583 भाग, 584 भाग, 585 भाग, 586 भाग, 587 भाग, 588 भाग, 589 भाग, 590 भाग, 591 भाग, 602 भाग, 608 भाग व 609 भाग ग्राम मगहुआँ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या 544 भाग, 546 भाग, 562 भाग, 563 भाग, 561 भाग ,560 भाग, 569 भाग, 570 भाग, 581 भाग, 582 भाग, 651 भाग, 679 भाग, 680 भाग, 681 भाग, 682 भाग, 690 भाग, 692 भाग व 766, ग्राम-बेली, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं खसरा संख्या 94, ग्राम हबुवापुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं गोसाईगंज-मोहनलालगंज मुख्य मार्ग।

दक्षिण—मुख्य शारदानहर (इन्दिरा कैनाल) खसरा संख्या-४६ ग्राम-हबुवापुर परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या ४८८ व १८६ ग्राम सिद्धपुरा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं ३७० भाग ग्राम भटवारा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पश्चिम—मुख्य शारदा नहर (इन्दिरा कैनाल) व खसरा संख्या 379 भाग, ग्राम भटवारा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं खसरा संख्या 280 भाग, 282 भाग, 283 भाग, 275 भाग, 260 भाग, 258 भाग, 257 भाग, 256 भाग, 255 भाग, 254 भाग, 251 भाग, 202 भाग, 200 भाग, 133 भाग, 135 भाग, 136 भाग, 143 भाग, 139 भाग, 98 भाग, 81 भाग, 97 भाग, 82 भाग, 80, 83 भाग व 84 भाग ग्राम पहाड़नगर टिकरिया, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-09, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक देखे जा सकते है।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों व योजना की सीमा के 500.00 मीटर के अन्तर्गत आने वाली भूमि/निर्माण के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपित्तयों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-9, उ०प्र० आवास विकास परिषद, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपित्त स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपित्त में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपित्तकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रुप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद, आवास आयुक्त।

NOTICE

(Notice under section 28 of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965 (Uttar Pradesh Act No. 1, 1966)

[Land Aqusition Section]

15 February, 2024

No. 1381/L.A.C./H.Q.—U.P. Awas Evam Vikas Parishad Framed a housing scheme "Bhoomi Vikas Evam Grah-Asthan Yojana No. 01 Mohanlalganj, Lucknow" to solve the increasing housing problem of Lucknow city. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-

North-On Lucknow-Sultanpur-Varanasi railway line, Khasra No-3094 village-Bakkas, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No-85 village Paharnagar Tikariya, Pargana & Tehsil-Mohanlal Ganj, Lucknow and Khasra No-477 and 476, village Moazzamnagar, Pargana. & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-315, 314/529, 296/528, Village Kabirpur, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-847, 845 Part, 856, Village Kasimpur Biruha, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-493 and 523, Village Chand Sarai, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-326, Village Maghuaan, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.

East-Khasra Number-325 Part, 295 Part, 298 Part, 297 Part, 299 Part, 300 Part, 320 Part, 302 Part, 292 Part, 303 Part, 307 Part, 306 Part, 304 Part, 289 Part, 395 Part, 396 Part, 397 Part, 408 Part, 409 Part, 410 Part, 414 Part, 416 Part, 415 Part, 509 Part, 511 Part, 512 Part, 522 Part, 521, 520 Part, 527 Part, 529 Part, 533 Part, 534 Part, 537, 578 Part, 581 Part, 582 Part, 583 Part, 584 Part, 585 Part, 586 Part, 587 Part, 588 Part, 589 Part, 590 Part, 591 Part, 602 Part, 608 Part, & 609 Part of village Magahuan, Pargana and Tehsil -Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No. 544 Part, 546 Part, 562 Part, 563 Part, 561 Part, 560 Part, 569 Part, 570 Part, 581 Part, 582 Part, 651 Part, 679 Part, 680 Part, 681 Part, 682 Part, 690 Part, 692 Part & 766 Village Bailey, Pargana and Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No. 94, Village Habuvapur, Pargana and Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Gosaiganj-Mohanlalganj main road.

South: Main Shardanahar (Indira Canal) Khasra No. 46 village - Habuvapur Pargana & Tehsil - Mohanlalganj, Lucknow and Khasra number 488 and 186 village Siddhpura, Pargana & Tehsil - Mohanlalganj, Lucknow and 379 Part village Bhatwara, Pargana & Tehsil - Mohanlalganj, Lucknow.

West: Main Shardanahar (Indira Canal) and Khasra Number 379 Part Village Bhatwara, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No. 280 part, 282 part, 283 part, 275 part, 260 part, 258 part, 257 part, 256 part, 255 part, 254 part, 251 part, 202 part, 200 part, 133 part, 135 part, 136 part, 143 part, 139 part, 98 part, 81 part, 97 part, 82 part, 80, 83 part and 84 part village Paharnagar Tikariya, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.

The details of the land incorporated in the scheme and map can be seen in the office of Housing Commissioner(Land Acquisition Section), U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow on any working day from 11:00 AM to 2:00 PM.

The Land owners of the structures situated in the scheme and land/structure within 500.00 metre of the boundary of the scheme will also be liable to pay betterment fee/development charges according to requisite rules/provisions of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.

The objections against the scheme shall be received at the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow within 30 days from the first publication of this notice in Gazatte Uttar Pradesh. After the due date, no objection will be accepted. The objection so submitted should clearly mark out the correct Name of the Scheme and the Land/Building/Village Name/Khasra Number/Area of the land of the objector incorporated in the scheme and all other details.

RANVIR PRASAD, *Housing Commissioner.*

कार्यालय, नगर पंचायत, बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ नगर पंचायत बूढनपुर, जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र में भवनों के निर्माण, पूर्ननिर्माण, मरम्मत अथवा उनके विस्तार सम्बन्धी उप विधि, 2021

दिनांक 01 फरवरी, 2024 ई0

सं० २४४ / न०पं०बूद० / उपविधि प्रकाशन-३ / २०२३-२४ - उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या २८६६ / १-१-2019—11टी0ए0 / 19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं उसका प्रादेशिक क्षेत्र घोषित हो जाने के फलस्वरूप उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद-आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र (Territorial Area) में स्थित में भवनों के निर्माण पूर्ननिमार्ण मरम्मत अथवा उसके विस्तार सम्बन्धी निर्धारण किये जाने हेतू निम्न नियमावली बनायी गयी थी। प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव यदि कोई हो प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बूढ़नपुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए जो समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर नगर पंचायत बूढ़नपुर के कार्यालय में प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक संख्या 24/न0पं0 बूढ़नपुर दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक देवब्रत में प्रकाशित कराया गया था, निर्धारित समयाविध में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है। पुनः नवसृजित निकाय की प्रथम निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त गठित निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 16 जून, 2023 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा प्रस्तावित उपविधि को अंगीकार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया। तत्क्रम में पुनः आपत्ति / सुझाव हेतु कार्यालय नगर पंचायत बूढ़नपुर के पत्र संख्या 114 / न0पं0बूढ़ / 2023–24 दिनांक 29 सितम्बर, 2023 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं स्थानीय समाचार-पत्र रणपूजा में प्रकाशित कराया गया, निर्धारित समयावधि में कोंई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए निकाय द्वारा बनायी गयी उपविधि को शासकीय सरकारी गजट में प्रकाशित कराये जाने हेतू प्रेषित किया जा रहा, उपविधि सरकारी गजट के प्रकाशन के तिथि से प्रभावी होगा:--

आदेश

उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 2866/9—1—2019—11टी०ए०/19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं उसका प्रादेशिक क्षेत्र घोषित हो जाने के फलस्वरूप उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र (Territorial Area) में भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में यह उप विधि बनायी जाती है:—

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ-

1—उप विधि का नाम—नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र में भवनों के निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत अथवा उनके विस्तार सम्बन्धी उप विधि 2021 के नाम से जानी जायेगी।

2-यह उप विधि नगर पंचायत बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में लागू होगी।

3—यह उप विधि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 अथवा राजकीय गजट में प्रकाशन/प्रकाशित होने के दिनांक जो पहले होगा लागू होगी।

परिभाषाये –

1—नगर पंचायत बूढ़नपुर का तात्पर्य उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 2866 / 9—1—2019—11टी०ए० / 19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा घोषित नगर पंचायत बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ से है।

- 2-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- 3-शासन का तात्पर्य उ०प्र० शासन से है।
- 4-अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अध्यक्ष से है।
- 5-प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के प्रशासक से है।

6-अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

7—अवर अभियन्ता, सदस्य, लिपिक, कर समार्हता, सफाई नायक, सुपरवाइजर का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अवर अभियन्ता, सदस्य, लिपिक, कर समार्हता, सफाई नायक, सुपरवाइजर से है, चाहे उनकी सेवायें जिस रूप में ली जा रही है।

8—ड्राफ्टमैन (नक्शा नवीस) का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत ड्राफ्टमैन (नक्शा नवीस) से है।

9—भवन का तात्पर्य ऐसे प्रस्तावित, निर्माणाधीन, भवनों, दुकानों कोठरियों आदि समस्त प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माण से है जो नगर पंचायत बूढ़नपुर के प्रादेशिक क्षेत्र में निर्माण/पुर्ननिर्माण/मरम्मत कराये जाने वाले हो।

नियम—

1—नगर पंचायत बूढ़नपुर के सीमान्तर्गत भवनों, दुकानों कोठिरयों आदि समस्त प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माण के लिए मानिचत्र (ले-आउट प्लान) एवं निर्माण पर लागत का मूल्यांकन करने हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा ऐसे ड्राफ्टमैन (नक्शा नवीस) को नामित किया जायेगा जो ड्राफ्टमैन के लिए निर्धारित योग्यता रखता हो। अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित ड्राफ्टमैन पंजीकरण के समय रु० 5,000.00 शुल्क जमा करेगा और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए उसे प्रति वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल में रु० 2,500.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा। ड्राफ्टमैन द्वारा सार्वजिनक उपयोग की भूमि अथवा उसके भाग यथा सड़क, गली, रास्ता उसकी पटरी, नाली और सरकारी जमीन पर स्थाई/अस्थाई निर्माण के लिए मानिचत्र नहीं बनाया जायेगा। ऐसा करने पर अध्यक्ष, प्रशासक, अधिशासी अधिकारी द्वारा ड्राफ्टमैन की अधिकारिता समाप्त कर दी जायेगी और यथोचित अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा रु० 25,000.00 होगी। ड्राफ्टमैन द्वारा निर्माणकर्ता से अपनी श्रम शक्ति एवं लेखन सामाग्री की फीस ली जायेगी जो प्लान के आधार पर होगी और जिसकी अधिकतम धनराशि रु० 2500.00 प्रति मानिचत्र से अधिक नहीं होगी। ड्राफ्टमैन द्वारा इससे अधिक फीस लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर और जाँच में सही पाये जाने पर ड्राफ्टमैन की अधिकारिता समाप्त कर दी जायेगी।

2—ड्राफ्टमैन द्वारा बनाये गये मानचित्र पर भू-खण्ड स्वामी / स्वामियों का नाम पिता का नाम पता अंकित किया जायेगा जिस पर भू-खण्ड / भवन के स्वामी / स्वामियों के हस्ताक्षर होगें।

3—ड्राफ्टमैन द्वारा बनाये गये मानचित्र एवं निर्माण की लागत की मूल्यांकन पर एक प्रतिशत शुल्क के साथ नगर पंचायत कार्यालय में स्वामी द्वारा जमा की जायेगी।

4—नगर पंचायत के कार्यालय में प्राप्त मानचित्र के आधार पर उसके स्वामित्व की जॉच के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित अवर अभियन्ता, सदस्य, लिपिक, कर समार्हता, सफाई नायक, सुपरवाइजर जॉच करेगा और स्वामित्व तथा स्थलीय निरीक्षण की जॉच करने के उपरान्त अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा। भवन निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष / प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बूढनपुर को होगा।

5—स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य पाये जाने पर या बिना नक्शा स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किये जाने पर उसे अनिधकृत निर्माण माना जायेगा एवं किसी प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर स्वीकृत मानचित्र को अध्यक्ष / प्रशासक अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा और ऐसे हुये समस्त प्रकार के निर्माण को उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम की धारा 186 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ध्वस्त करा दिया जायेगा तथा ध्वस्तीकरण कार्य में उपयोग में लायी जाने वाली श्रम / तकनीकी शक्ति में हुये व्यय की भू-राजस्व की भॉति वसूली अनिधकृत निर्माणकर्ता से की जायेगी।

शास्ति

उ०प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि जो व्यक्ति इस उप विधि का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे कम से कम रु० 1,000.00 और अधिकतम रु० 25,000.00 के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जायेगा और उप नियम (1) में

निर्दिष्ट किसी बात के होते हुये भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिए अर्थदण्ड की अन्यून तिहाई धनराशि और अनधिक आधी धनराशि की वसूली पर अध्यक्ष / प्रशासक / अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

प्रस्तावित उप विधि के सम्बन्ध में आपित्तयाँ या सुझाव यदि कोई हो प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बूढ़नपुर को सम्बोधित करते हुये लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए जो समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर नगर पंचायत बूढ़नपुर के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत अविध के बाद प्राप्त आपित्तयों और सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आपित्तयों एवं सुझावों पर विचार कर निस्तारण करने के उपरान्त यह उप विधि राजकीय गजट में प्रकाशन होने के दिनांक अथवा 01 अप्रैल, 2021 जो भी पहले होगा से लागू हो जायेगी।

मंशा, अध्यक्ष, नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ।

नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र में मछली, बकरे तथा मुर्गे का गोश्त विक्रय करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित और शासन के निर्देशों के अनुरूप दुकानों की स्थापना से सम्बन्धित उपविधि 2021

दिनांक 01 फरवरी, 2024 ई0

सं० २४४ / न०पं०बूढ़० / उपविधि प्रकाशन—३ / २०२३—२४—उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या २८६६ / १—1— 2019—11 टी०ए० / 19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं उसका प्रादेशिक क्षेत्र घोषित हो जाने के फलस्वरूप उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र (Territorial Area) में स्थित में भवनों के निर्माण पूर्निनमार्ण मरम्मत अथवा उसके विस्तार सम्बन्धी निर्धारण किये जाने हेतू निम्न नियमावली बनायी गयी थी। प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव यदि कोई हो प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बूढ़नपुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए जो समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर नगर पंचायत बूढ़नपुर के कार्यालय में प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक संख्या 24/न०प० बुढनपुर दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक देवब्रत में प्रकाशित कराया गया था, निर्धारित समयाविध में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है। पुनः नवसृजित निकाय की प्रथम निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त गठित निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 16 जून, 2023 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा प्रस्तावित उपविधि को अंगीकार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया। तत्क्रम में पुनः आपत्ति / सुझाव हेतु कार्यालय नगर पंचायत बूढ़नपुर के पत्र संख्या 115 / न0पं0बूढ़ / 2023–24 दिनांक 29 सितम्बर, 2023 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं स्थानीय समाचार-पत्र रणपूजा में प्रकाशित कराया गया, निर्धारित समयावधि में कोंई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए निकाय द्वारा बनायी गयी उपविधि को शासकीय सरकारी गजट में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा, उपविधि सरकारी गजट के प्रकाशन के तिथि से प्रभावी होगा—

आदेश

उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 2866 / 9-1-2019-11टी०ए० / 19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं उसका प्रादेशिक क्षेत्र घोषित हो जाने के फलस्वरूप उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र (Territorial Area) में मछली एवं बकरे तथा मुर्गे का गोश्त विक्रय करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित और शासन के निर्देशों के अनुरूप दुकानों की स्थापना हेतु यह नियमावली बनायी जाती है:-

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ–

- 1—उप विधि का नाम—नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र में मछली, बकरे तथा मुर्गे का गोश्त विक्रय करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित और शासन के निर्देशों के अनुरूप दुकानों की स्थापना से सम्बन्धित उपविधि 2021 के नाम से जानी जायेगी।
 - 2-यह उप विधि नगर पंचायत बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र में लागू होगी।
- 3—यह उप विधि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 अथवा राजकीय गजट में प्रकाशन/प्रकाशित होने के दिनांक जो पहले होगा लागू होगी।

परिभाषायें—

- 1—नगर पंचायत बूढ़नपुर का तात्पर्य उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 2866 / 9—1—2019—11टी०ए० / 19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा घोषित नगर पंचायत बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ से है।
 - 2-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
 - 3-शासन का तात्पर्य उ०प्र० शासन से है।
 - 4-अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अध्यक्ष से है।
 - 5-प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के प्रशासक से है।
 - 6—अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अधिशासी अधिकारी से है।
- 7—नगर स्वास्थ्य अधिकारी का तात्पर्य प्रा०स्वा०केन्द्र कोयलसा के प्रभारी चिकित्साधिकारी अथवा ऐसे चिकित्साधिकारी से है जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित किया गया हो।
- 8-पशु चिकित्साधिकारी का तात्पर्य ऐसे पशु चिकित्साधिकारी से है जिसे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नगर क्षेत्र बूढ़नपुर के लिए नामित किया गया हो।
- 9—लिपिक, कर समार्हता, सफाई नायक, सुपरवाइजर का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अवर लिपिक, कर समार्हता, सफाई नायक, सुपरवाइजर से है, चाहे उनकी सेवायें जिस रूप में ली जा रही है।
- 10—मछली का तात्पर्य ऐसे जीवित मछलियों से है जो विक्रय के लिए उपयुक्त हो और गोश्त का तात्पर्य ऐसे बकरे एवं मुर्गे से है जिन पर वर्ड फ्लू जैसे बिमारी का प्रभाव न हो।

नियम-

नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र (Territorial Area) में मछलियों बकरे एवं मुर्गे के गोश्त का विक्रय करने की अनुमित के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को सम्बोधित करते हुये प्रार्थना-पत्र दिये जायेगें जिनकी जॉच के लिए नियम 7 में उल्लिखित कर्मचारियों में से अधिकृत कर्मचारी द्वारा की जायेगी और निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुये आख्या उपलब्ध करायी जायेगी:—

- 1-विक्री के लिए प्रस्तावित स्थल सार्वजनिक उपयोग का नहीं है।
- 2—विक्री के लिए प्रस्तावित स्थल आवेदक का स्वयं का है या किराये पर लिया गया है। अगर किराये पर लिया गया है तो उस व्यक्ति का उप निबन्धक बूढ़नपुर द्वारा किरायेदारी के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुबन्ध-पत्र।
- 3—आवेदक द्वारा बकरे एवं मुर्गे के गोश्त को खुले में विक्री न करने एवं लाल कपड़े से ढक कर रखने का नोटरी शपथ-पत्र।
- 4—बकरे / मुर्गे के गोश्त के विक्रय हेतु प्रस्तावित स्थल की प्रकृति स्थाई दुकान है या गुमटी है से सम्बन्धित विवरण।
- 5—मछली, बकरे एवं मुर्गे के गोश्त विक्रय के उपरान्त उत्पन्न कचरा के निस्तारण की व्यवस्था से सम्बन्धित शपथ-पत्र। इस बिन्दु पर जॉच करने वाले कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विक्रय के उपरान्त उत्पन्न कचरे को नगर क्षेत्र के बाहर आवादी से दूर जमीन के भीतर निस्तारण करने का स्थान आवेदक के पास उपलब्ध है।
- 6—उक्त नियम 1 से 5 की शर्तो को पूर्ण किये जाने पर आवेदक से रु० 500.00 वार्षिक लाइसेंस शुल्क लेकर रसीद दी जायेगी जो आवेदक का लाइसेंस होगा।
- 7—अध्यक्ष / प्रशासक / अधिशासी अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थल पर विक्रय करने के लिए दिये गये लाइसेंस के सम्बन्ध में भी नियम 3 से 6 प्रभावी होगा।

शास्ति

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि जो व्यक्ति इस उप विधि का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे अधिकतम रु० 1,000.00 के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जायेगा और उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुये भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिए अर्थदण्ड की अन्यून तिहाई धनराशि और अनिधक आधी धनराशि की वसूली पर अध्यक्ष / प्रशासक / अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

प्रस्तावित उप विधि के सम्बन्ध में आपित्तयाँ या सुझाव यदि कोई हो प्रशासक/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बूढ़नपुर को सम्बोधित करते हुये लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए जो समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर नगर पंचायत बूढ़नपुर के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत अविध के बाद प्राप्त आपित्तयों और सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आपित्तयों एवं सुझावों पर विचार कर निस्तारण करने के उपरान्त यह उप विधि राजकीय गजट में प्रकाशन होने के दिनांक अथवा 01 अप्रैल, 2021 जो भी पहले होगा से लागू हो जायेगी।

मंशा, अध्यक्ष, नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ।

नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद—आजमगढ़ के प्रादेशिक में निष्पादित किये जाने वाले विलेख पत्रों स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखें पर कर उगाहने से सम्बद्ध उपविधि, 2023

दिनांक 01 फरवरी, 2024 ई0

सं0 244 / न0पं0बूढ़0 / उपविधि प्रकाशन—3 / 2023—24—नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 ऐक्ट संख्या-2, 1916) की धारा 128 (1) के उपखण्ड (13ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2023 प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा नियमावली बनयी गयी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 131(3) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है, जिसकी अविध 01 माह अर्थात 30 दिवस होगी। आपत्ति / सुझाव हेतु कार्यालय नगर पंचायत बूढ़नपुर के पत्र संख्या 98 / न0पं0बूढ़0 / 2023—24 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण दिनांक 06 सितम्बर, 2023 में प्रकाशित कराया गया, निर्धारित समयाविध में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नही हुए निकाय द्वारा बनायी गयी उपविधि को शासकीय सरकारी गजट में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा, उपविधि सरकारी गजट के प्रकाशन के तिथि से प्रभावी होगा।

नियमावली

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ प्रवृत्ति—

- (1) यह नियमावली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखें पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली 2023 कहलायेगी।
- (2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जायें।
- (3) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

- 2-परिभाषाएं-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-
- (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू०पी० अधिनियम संख्या—2, सन 1916) से है।
 - (ख) "नगर" का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ से है।
- (ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 (एक्ट संख्या 2, सन 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।
- (घ) ''इण्डियन स्टाम्प एक्ट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899) से है।
 - (ड़) "नगर पालिका / नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत बूढनपुर जनपद आजमगढ़ से है।
 - (च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर के अधिशासी अधिकारी से है।
 - (छ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ से है।
- (ज) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।
- 1—नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढा दिया जायेगा।
- 2—कर के लेखे रखना—निबंधक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक, पृथक लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क व कर दिखायेगा।
- 3—निबंधक अधिकारी, जो दिवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या 16 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या 1 में नर्त्थ करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेगें।
- 4—निबंधक अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक-पृथक तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबंधक को उपयुक्त प्रत्येक महीने के पाँचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।
- 5—जिला निबंधक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के 10वे दिनांक तक तिमाही विवरण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित को भेजेगा।
 - (1) निबंधक, महानिरीक्षक, उ०प्र० इलाहाबाद।
 - (2) अपर सचिव, राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद।
 - (3) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़।
 - (4) महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
- 1—(1) नगर पंचायत बूढ़नपुर की ओर से उगाही कर धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत बूढ़नपुर को लौटा दी जायेगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ प्रत्येक तिमाही में किनष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद को फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या-19 में दों प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, किनष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

- (2) पालिका निबंधक और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक / पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।
- (3) कर लगाने की प्रक्रिया—उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका / नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।
- 1—अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबंधक के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबंधक अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरा—

निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक दिये गये है-

- (क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और
- (ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।
- 1—यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक-पृथक व दिये गयें हो तो निबंधक अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।
- 1—अभिलेख का निरीक्षण—अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धक कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।
- 2—इस उप नियमावली की उपरोक्त किसी भी उपधारा में किसी प्रकार का संशोधन का अधिकार अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष में निहित होगा।

शास्ति

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद—आजमगढ़ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपबंधों का उल्लंघन अर्थदण्ड लिया जायेगा, जो रू० 10,000.00 हो सकता है।

मंशा, अध्यक्ष, नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ।

नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र में विविध कर/शुल्क/ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/शमन उपविधि, 2023

उपविधि सूचना

दिनांक 01 फरवरी, 2024 ई0

सं0 244 / न०पं०बूढ़० / उपविधि प्रकाशन—3 / 2023—24—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2) व अन्य अधिकारों का प्रयोग कर के नगर पंचायत बूढ़नपुर सीमा अन्तर्गत ठोस अपिशष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 के नियम—15 (ड़) के अनुरूप नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन निम्नलिखित प्रकार की उपविधि बनाने हेतु नगर पंचायत बूढ़नपुर निकाय बोर्ड बैठक दिनांक 16 जून, 2023 प्रस्ताव संख्या 05 अनुमोदन किया गया। उक्त के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण, स्वतंत्र चेतना में विज्ञप्ति प्रकाशित निकाय के सभी निवासियों / हितबद्ध / जनमानस के संज्ञानार्थ प्रकाशित कराया जा रहा है कि अपना आपत्ति / सुझाव प्रकाशन के

30 दिवस के भीतर कार्यालय नगर पंचायत बूढ़नपुर में दर्ज करा सकते है। आपित / सुझाव हेतु कार्यालय नगर पंचायत बूढ़नपुर के पत्र संख्या 118 / न0पं0बूढ़0 / 2023—24 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण, स्वतंत्र चेतना दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 में प्रकाशित कराया गया, निर्धारित समयाविध में कोई आपित / सुझाव प्राप्त नही हुए निकाय द्वारा बनायी गयी उपविधि को शासकीय सरकारी गजट में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा, उपविधि सरकारी गजट के प्रकाशन के तिथि से प्रभावी होगा।

1–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

- 1—नाला / नाली सार्वजनिक जगह / नगर पंचायत के स्वामित्व की भूमि / भवन पर / सामने गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु० 100.00 प्रति प्रकरण देय होगा, तथा पुनरावृत्ति करने / पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु० 500.00 प्रति प्रकरण देय होगा।
 - 2-मरे हुए बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु० 1000.00 प्रति पशु देय होगा।
 - 3-मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर शुल्क रु० 500.00 प्रति पशु देय होगा।
- 4-शादी / विवाह या अन्य कोई शुभ कार्यो हेतु आयोजित समारोह / कार्यक्रम की सफाई हेतु शुल्क रु० 1,000.00 प्रति प्रकण देय होगा। किन्तु धार्मिक कार्यो हेतु आयोजित समारोह / कार्यक्रम इस शुल्क से मुक्त होंगे।
- 5—चाट/फास्ट फूड/फल आदि खाद्य पदार्थों के ठेले आदि के साथ डस्टबीन/कूड़ादान होना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने/होने पर शुल्क रु० 100.00 प्रति प्रकरण देय होगा।
- 6—कूड़ा कचरा जलायें जाने पर जुर्माना रु० 500.00 एवं पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 प्रति प्रकरण देय होंगा। यह जुर्माना शुल्क समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये अर्थदण्ड के अतिरिक्त होगा।
- 7—नगर पंचायत के अनुमित के बिना सड़क के किनारे भवन निर्माण सामाग्री यथा-मोरंग, बालू, ईट, आदि या उसका मलवा पाये जानें पर समय—समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देश/अर्थदण्ड के अतिरिक्त जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 प्रति प्रकरण देय होगा।
- 8—नगर पंचायत की अनुमति के बिना नगर पंचायतों की सड़कों / फुटपाथों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना शुल्क रु० 1000.00 प्रति प्रकरण होगा। क्षतिग्रस्त सड़कों / फुटपाथों की मरम्मत पर आने वाला व्यय भार अतिरिक्त देय होगा।
- 2—शो टैक्स—नगर पंचायत सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसे स्वामीयों से रुठ 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।
 - 3-विज्ञापन कर-रु० ६.०० प्रति वर्ग फुट प्रति माह देय होगा।
- 4—ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पर शुल्क—(1) नगर पंचयात सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रांसफार्मर 250 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु० 5,000/ एवं 400 के0वी0एच0 क्षमता तक शुल्क रु० 10,000/—वार्षिक प्रति ट्रान्सफार्मर, 400 के0वी0 की अधिक की क्षमता के लिये रु० 25,000/— वार्षिक
 - (2) पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस / सब स्टेशन पर शुल्क रु० 50,000, वार्षिक।

5-नगर पंचायत बूढ़नपुर दुकान एवं बारात घर पर किराया शुल्क-

- 1-दुकान का किराया रु० 1,000.00 प्रति माह न्यूनतम।
- 2—बारात घर किराया रु० 5,000.00 पति दिन तथा कार्यक्रम के उपरान्त बारात घर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा।

6-अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क-

(1) मछली फुटकर बिक्री रु० 500.00 प्रति वर्ष।

- (2) मछली थोक बिक्री रु० 1,000.00 प्रति वर्ष।
- (3) फल फुटकर बिक्री रु० 500.00 प्रति वर्ष।
- (4) फल थोक बिक्री रु० २,०००.०० प्रति वर्ष।
- (5) सब्जी फुटकर बिक्री रु० 500.00 प्रति वर्ष।
- (6) सब्जी थोक बिक्री रु० २,०००.०० प्रति वर्ष।
- (7) अण्डा फुटकर बिक्री रु० 500.00 प्रति वर्ष।
- (8) अण्डा थोक बिक्री रु० २,०००.०० प्रति वर्ष।
- (9) मूर्गा, बकरा, भैंस, भैसा रु० 5,000.00 प्रति वर्ष।

7-विविध शुल्क की दरें-

- (1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु० ५०.०० पति प्रमाण-पत्र।
- (2) पानी टैंकर का किराया सादी विवाह एवं सामाजिक कार्य में रु० 500.00 मात्र नगर सीमा के अन्दर तथा नगर सीमा से 4 कि0मी0 तक रु० 700.00 मात्र एवं 4 कि0मी0 से 10 कि0मी तक रु० 1,000.00 मात्र शुल्क लगेगा।
- (3) नगर सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु० ८००.०० प्रति टैंकर पतिदिन का शुल्क लगेगा।
- (4) सीवर सेक्शन मशीन के उपयोग हेतु नगर पंचायत सीमान्तर्गत रु० 2,000.00 मात्र प्रति चक्कर प्रति टैंकर तथा नगर सीमा के बाहर रु० 4,000.00 प्रति चक्कर प्रति टैंकर शुल्क लगेगा।
- (5) मोबाईल ट्वॉयलेट का किराया सादी विवाह एवं सामाजिक कार्य में रु० 3,000.00 मात्र नगर सीमा के अन्दर तथा नगर सीमा से बाहर रु० 5,000.00 मात्र शुल्क लगेगा।

8-अन्य व्यवसाय पर शुल्क-

- (1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रु० ३,०००.०० मात्र प्रति वर्ष।
- (2) नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोचिंग संस्थान पर रु० 1,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यवसायिक शुल्क रु० 10,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत रेस्टोरेन्ट ढाबा पर रु० २,000.00 प्रति वर्ष।
- (5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आटा चक्की, तेल पेराई तथा रुई धूनाई मशीन पर रु० 1,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (6) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आरा मशीन, आईस फैक्ट्री पर रु० २,०००.०० मात्र प्रति वर्ष।
- (7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत RO प्लांट एव निजि जलापूर्ति पर रु० 2,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत मोटरसाईकित एजेन्सी एवं ट्रैक्टर एजेन्सी पर रु० 3,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत ईंट भट्ठों पर रु० 10,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त बैंकों पर रु० 5,000.00 प्रति वर्ष।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सेट्रींग व तक्था, बल्ली कड़िया पर रु० २,०००.०० मात्र प्रति वर्ष।
- (12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत देशी शराब की दुकान पर रु० 5,000.00 मात्र प्रति वर्ष।

- (13) नगर पंचायत सीमान्तर्गत विदेशी शराब की दुकान पर रु० 10,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत बार / बियर की दुकान पर रु० 10,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (15) नगर पंचायत सीमान्तर्गत मॉडल शाप की दुकान पर रु० 15,000.00 मात्र प्रति वर्ष।
- (16) नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण हेतु सामग्री जैसे—सीमेन्ट, सरिया, मोरंग, बालू इत्यादि पर रु0 5,000.00 मात्र प्रति वर्ष।

9-अन्य शुल्क एवं जुर्माना-

- (1) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु यूजर चार्ज रु० २०.०० मात्र घरेलू एवं व्यवसायिक पर रु० ५०.०० मात्र।
- (2) जल कनेक्शन के लिए रोड कटिंग चार्ज रु० 2,000.00 मात्र प्रति कनेक्शन एवं जमानत राशि रु० 500.00 पति कनेक्शन।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत जे०सी०बी० किराया रु० 1,000.00 मात्र प्रति घण्टा एवं बाहर जाने आने पर समय शुल्क।
 - (4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत शव वाहन रु० ३००.०० मात्र तथा बाहर जाने पर रु० 1,०००.०० मात्र
 - (5) सार्वजनिक स्थानों, नाला / नालियों में कूड़ा कचरा एवं गंदगी फैलाने पर रु० 500.00 मात्र जुर्माना।
- (6) एन0जी0टी0 एक्ट 2010 की धारा 15, 16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खूले में कूड़ा जलाने पर अर्थ दण्ड प्रति प्रकरण रु० 5,000.00 मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने व मलबा रखे जाने पर रु० 50,000.00 मात्र का जुर्माना वसूल किया जायेगा।
- (7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नाला / नाली सड़क एवं अन्य सार्वजनिक सम्पित्त पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी रुठ 1,000.00 मात्र प्रति प्रकरण तथा पुर्नवृत्ती करने पर रुठ 5,000.00 मात्र प्रति प्रकरण जुर्माना लगेगा।
- (8) छोटी बाउन्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पडोसियों के द्वारा कूड़ा-कचरा फेकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउन्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मीटर उची बाउन्ड्रीवाल न कराने पर रु0 2,500.00 मात्र का जुर्माना लगेगा।
- (9) गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पाल्तू जानवरों को खूला छोड़ने पर पकड़े जाने पर रु० 1,000.00 मात्र प्रति प्रकरण प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।
- (10) सी0 एण्ड0 डी0 वेस्ट नगर पंचायत द्वारा उठाने पर रु० 200.00 मात्र प्रति ट्राली जुर्माना लगेगा। तथा प्रयोग हेतु नगर पंचायत से लेने पर रु० 100.00 मात्र देय होगा।
- (11) वेट वेस्ट कूड़े से बने खाद् को नगर पंचायत से खरीदारी करने पर रु० 500.00 मात्र प्रति ट्राली देय होगा।
- (12) ठेकेदार का पंजीकरण रु० 15000.00 प्रति वर्श तथा नवीनीकरण हेतु रु० 5,000.00 मात्र वार्षिक शुल्क लगेगा।
- 10 उपरोक्त उपविधि के किसी बिन्दु में कोई परिर्वतन/संसोधन करने के लिए सक्षम अधिकारी निर्णय ले सकेगे, जिसका पुनः गजट में प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा।

शास्ति / दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ यह आदेश देती है कि:—

1—जो व्यक्ति इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, उसे रू० 1,000.00 (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किये जाने की स्थिति में प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येंक दिवस के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करना सिद्ध होगा, रु० 50.00 (पचास रुपये) तक हो सकेगा।

2— उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिए नियत अर्थदण्ड की अन्यून तिहाई धनराशि और अनधिक आधी धनराशि की वसूली पर अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा किसी नामित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

मंशा, अध्यक्ष, नगर पंचायत बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ।

कार्यालय नगर पंचायत गोहाण्ड-हमीरपुर

पशु बाजार उपविधि

16 दिसम्बर, 2023 ई0

815 / न०पं०गो० / पशु बाजार उपविधि (23-24)—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीर पुर जिस उप विधि बनाने का प्रस्ताव करता है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 कि अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उनके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एत्दद्वारा प्रकाशित किया गया है जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार प्रत्र अमर उजाला में दिनांक 19 नवम्बर, 2023 को कराया गया निर्धारित अविध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुए है। अतः यह उप विधि म्यूनिस्पल एक्ट कि धारा 301 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित कि जाती है जो गजट में मुद्रण तिथि से प्रभावी होगी।

उपनियम (उपविधि)

परिभाषा-

नगर पंचायत गोहाण्ड हमीरपुर के सीमा के अन्दर पशु बाजार लगाने का अभिप्राय है कि किसी निश्चित स्थान पर पशु बाजार का लगाया जाना तथा पशु क्रय विक्रय का तात्पर्य है कि पशु क्रय विक्रय करने वाले व्यक्तियों के आपसी समझौते में जो बातचीत अन्तिम हो पशुबाजार नियन्त्रण से तात्पर्य है। किसी भी स्थान पर बाजार लगाया जाये उसका नियंत्रण नगर पंचायत द्वारा किये जाने से है।

1–पशु बाजार से तात्पर्य है जो नगर पंचायत में सप्ताह में एक बार बाजार लगाया जाये तथा उसमें किसी प्रकार से पशुओं को खरीदा तथा बेचा जा सकता है।

2.-नगर पंचायत बोर्ड से नगर पंचायत गोहाण्ड का तात्पर्य है।

3—संबन्धित का तात्पर्य है नगर पंचायत गोहाण्ड के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अनुयसमिति कर्मचारी से होगा। 4—पशुओं का तात्पर्य गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरा-बकरी, भेड़ सुअर तथा उक्त सभी जानवरों के बच्चों को शामिल करते हुए सभी जानवरों जो पशु बाजार में विक्रय/क्रय हेतु आयेंगे । पक्षियों की बिक्री हेतु पर भी वह नियम लागू होगा।

5— पशु बाजार लगाने हेतु नगर पंचायत स्वतः अपनी जमीन हरदौल लाला के पास अथवा पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही पशु बाजार लगायेगी।

6-कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत गोहाण्ड हमीरपुर सीमा के अन्दर पशु बाजार बिना पंचायत की अनुमित से नहीं लगा सकता हैं। जब तक कि पशु बाजार लगाने के लिए पंचायत से लिखित न प्राप्त कर लिया हो।

7—यह कि जो व्यक्ति इन नियमों के पूर्व नगर पंचायत गोहाण्ड के सीमा के अन्दर पशु बाजार लगाते रहे हैं। उन पर भी यह नियम लागू होंगे। और पंचायत के पशु बाजार लगाने की अनुमति प्रदान करनी होगी।

8—जो व्यक्ति पशु बाजार लगवायेगा उसको निर्धारित की गई धनराशि से अधिक वसूल करने के अधिकार नहीं होंगा। पशु बाजार का स्थान काटी गई रसीद क्रय विक्रय किये हुये आपसी समझौते दलीलों के लाइसेन्स आदि का निरीक्षण करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष अथवा पशु बाजार के लिए नियुक्ति कर्मचारी होगा।

9—यह कि पशु बाजार में नगर पंचायत के बाहर से जानवर लाने वाले व्यक्तियों को नगर पंचायत से निर्धारित प्रपत्र में सूचना देनी होगी जो कि परिशिष्ट नम्बर (1) में है।

10—यह कि पशु खरीदने वाले व्यक्ति को खरीदने के प्रमाण-पत्र निर्धारित शुल्क देकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शुल्क परिशिष्ट नम्बर (1) के अनुसार होगा। प्रपत्र ख का प्रमाण-पत्र न होने पर पशु का क्रय विक्रय अवैध माना जायेगा।

11—पशु बाजार लगाने वाला व्यक्ति पशु क्रेता एवं विक्रेता को असुविधायें देता है और नगर पंचायत को इसकी लिखित सूचना मिलती है तो नगर पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह पशु बाजार लगाने की स्वीकृति अथवा ठेका को निरस्त कर दें। और समिति स्वयं अपना बाजार लगवाना प्रारम्भ कर सकती है।

12—पशु बाजार में यदि कोई व्यक्ति दलाली करना चाहता हो तो उसे भी नगर पंचायत से मु0 रु0 500/— वार्षिक शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त करना होगा। बिना लाइसेन्स के कोई भी दलाली नहीं की जा सकती है। दलाली करने वाला व्यक्ति रु0 50/- से अधिक दलाली नहीं करेगा। तथा दलालों की धनराशि का 1/2 भाग नगर पंचायत को अदा करेगा।

13—इन उप नियमों के बोर्ड द्वारा पारित होने के बाद से नगर पंचायत गोहाण्ड के निवासी को किसी भी व्यक्ति को बिना नगर पंचायत की आज्ञा के अपना निजी रुप से पशु बाजार नहीं लगाया जा सकता है।

14—नगर पंचायत को इन उपनियमों को मंजूर होने के बाद यह अधिकार होगा कि नगर पंचायत यदि चाहे तो स्वतंत्र या एक वर्ष के लिये अस्थाई नीलाम पर ठेका ले सकता है नीलाम प्राप्त कर्ता को यह अधिकार होगा कि वह समिति के नियमों के अन्तर्गत बाजार लगवायेगा। ठेकेदार द्वारा नीलाम स्वीकृत होने पर 1/3 धनराशि तुरन्त तथा शेष धनराशि निर्धारित किश्तों में जमा करना होगा अनिवार्य होगा। किश्ते न जमा करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

15—यदि नीलामी द्वारा पशु बाजार नगर पंचायत लगवाती है तो नीलाम प्राप्त कर्ता को यह आवश्यक होगा कि वह पशु बाजार में प्रयोग होने वाली रसीदों को नगर पंचायत लगवाती है तो नीलाम प्राप्त कर्ता को यह आवश्यक होगा कि वह पशु बाजार में प्रयोग होने वाली रसीदों को नगर पंचायत द्वारा प्रमाणित करवा कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित रिजस्टर में हस्ताक्षर करके प्राप्त करेगा। तथा उन्हीं रसीदों को प्रयोग में लायेगा और नगर पंचायत द्वारा स्वीकृति रेट भी होगा।

16—प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार में किसी भी पशु को खरीदने या बेचने के बाद बिक्री को तुरन्त रजिस्ट्रेशन करायेगा।

17-बिक्री कार्य प्रातः 8:00 बजे सुबह से शाम 5:00 बजे तक होगा।

18—कोई भी बिक्री करने वाला या खरीदने वाला या लिए हुए पशु अर्थात् तीनों में से किसी एक के नाम होने के दशा में रजिस्ट्री नहीं की जायेगीं बशर्ते कि बेचने वाला या खरीदने वाला स्वयं रजिस्ट्री के समय उपस्थित न हो सका तो उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि की उपस्थिति में भी रजिस्ट्री की जा सकती है।

19—नगर पंचायत नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा जो रजिस्ट्रेशन फीस ली जायेगी वह निम्न प्रकार होगी तथा प्रत्येक शनिवार को हरदौल लाला के पास बाजार लगाया जायेगा।

20—नगर पंचायत गोहाण्ड में शनिवार को पशु बाजार तथा सोमवार को क्रय-विक्रय, लोडिंग तथा निकासी भी होगी।

21—जो भी व्यक्ति पशु बाजार का प्रबंधन कार्य देखेगा अथवा पशु बाजार लगायेगा उसका यह दायित्व होगा कि पशु बाजार में आने वाले पशुओं में रुग्ण पशुओं की निगरानी रखेगा तथा उनके तात्कालिक इलाज हेतु समुचित व्यवस्था करेगा इसके अतिरिक्त बरसात अथवा अन्य दिनों में होने वाली सीजनली बीमारियां जैसे खुरपका, लम्पी रोग आदि के विस्तार को रोकने में समुचित प्रबन्ध करेगा।

शुल्क की दरें

पशु बाजार में प्रत्येक छोटे जानवरों एवं पक्षियों के प्रवेश पर प्रवेश शुल्क रु० 10.00 देय होगा तथा प्रत्येक बड़े जानवरों के प्रवेश पर प्रवेश शुल्क रु० 20.00 देय होगा।

पशु बाजार में छोटे जानवरों की बिक्री पर रु. 200.00 और बड़े जानवरों की बिक्री पर रु0 400 देय होगा।

22—रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियत फीस प्राप्त होने पर बिक्री पद के प्रति पूर्ण बिक्री सम्बन्धी समस्त ब्यौरा होगा और बिक्री-पत्र खरीददार को बिक्री की रजिस्ट्री प्रमाण रसीद स्वयं देगा प्रत्येक परिक्षेप के नीचे फीस का योग लगाया जायेगा।

23—यदि बेचने वाला या खरीददार को रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्वयं जानने पर भी दो साक्षियों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और साक्षी न मिलने पर उनका पूर्ण ब्यौरा न दर्ज होगा।

24— बिक्री-पत्र पर रजि0 अधिकारी बेचने वाले गवाहों का हस्तक्षेप करायेगा।

अधिकारी बिक्री-पत्र के साथ लगे कूपन को फाड़ कर रख लेगा और बिक्री कर खरीददार को वापिस कर देगा

दण्ड

इन नियमों की अवहेलना करने वालों को नगरपालिका परिषद की धारा 298 के आधीन रु० 1,000/— रुपया अर्थदण्ड दिया जा सकता है। यदि नियमों की अवहेलना बराबर जारी रही तो रु० 25/— प्रतिदिन की अवहेलना की तिथि के हिसाब के अतिरिक्त जुर्माना लिया जायेगा।

अनीता, अध्यक्ष, नगर पंचायत गोहाण्ड, हमीरपुर।

कार्यालय नगर पंचायत गोहाण्ड हमीरपुर

उत्तर प्रदेश नगर पंचायत गोहाण्ड हमीरपुर हेतु टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियम (Insatallation, Control and Regulation of Tower) सम्बन्धी आदर्श उपविधि एवं दिशा निर्देश

दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 823 / न0पं0गो0 / रा0ग0 (23-24)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन्1916) की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची—1 के आधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है ,उसका प्रारुप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उनके सम्बन्ध में आपित्तयों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया गया है जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को कराया गया, निर्धारित अवधि में कोई आपित्त एवं सुझाव प्राप्त नही हुऐ है अतः यह उपविधि म्यूनिस्पल एक्ट की धारा 301(2) के अर्न्तगत प्रकाशित की जाती है जो गजट में मुद्रण तिथि से प्रभावी होगी। 1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत गोहाण्ड (टावर स्थापना, नियंत्रण विनिमय) उपविधि 2014 कही जायेगी।
- (2) यह नगर पंचायत गोहाण्ड की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह गजट के प्रकाशित होने से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषायें-

- (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-
 - (एक) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।
- (दो) टावर से तात्पर्य रेडियों, दूरदर्शन, मोबाईल फोन या अन्य फोन या दूर संचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रिंमयां भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।
- (तीन) सेवा प्रदाता से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापी, संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिनके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।
- (चार) भवन के अन्तर्गत मकान घर के बाहर के कक्ष, छादक, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर ईंट लकड़ी मिट्टी धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो या इसके अन्तर्गत बरामदे चबूतरे मकानों की कुर्सियां दरवाजे और सीढ़ियां दीवालें तथा हाते की दीवालें और मेंड तथा ऐसी ही अन्य निर्माण भी हों।
- (पांच) भूमि के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थाई सूत्र से बंधी हुई वस्तुऐं और वे अधिकार है जो किसी सड़क विद्यायन द्वारा सृजित हुये हो।
 - (छह) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत गोहाण्ड से है।
- (2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हों। 3–प्रतिषेध
- (1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिसमें किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठिापित करेगा न परिनिर्मित करेगा न खड़ा करेगा न गाड़ेगा।
- (2) नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन या स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न

प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा न खड़ा करेगा न गाड़ेगा और नहीं किसी व्यक्ति कम्पनी, संस्था या उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा, न परिनिर्मित करने देगा, और न खड़ा करने देगा न गाड़ने देगा।

- (3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उसके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी तरह का कोई व्यवधान हो। 4—अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया
- (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे (धनराशि) रुपये भुगतान करके नगर पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। नगर पंचायत कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।
- (3) प्रत्येक आवेदन में ऐसी भूमि भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खड़ा किया जाना गाड़ा जाना या लटकाया जाना वांछित है।
- (4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट आवश्यक चित्र तथा संरचना संगड़ना प्रस्तुत की जायेगी।
- (5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि अथवा भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
- (6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्ति क्रम की स्थिति में टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- (7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊंचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य उपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियां अंकित की जायेंगी।
- (8) आटोमेटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सैट के निर्माता को जारी टाईप टेस्ट सर्टिफिकेट (Type test certificate) की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।
 - (9) ऊंचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से क्लियरिन्स प्राप्त किया जायेगा।
- (10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी। 5—अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें
- (1) किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्न लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी—
- (क) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो बसर्ते शुल्क इस उपविधि के आधीन संदत्त और जमा किया गया हो।
 - (ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।
 - (ग) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।
- (घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी कि समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।
- (ड़) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे, गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज / संरक्षित स्मारकों / भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

- (च) टावर के समीपस्थ भवनों के आवागमन प्रकाश और वातावरण में किसी भी रुप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा और नहीं लोक बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न की जायेगी।
- (ज) ढांचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित टावर को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।
- (झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले बेस ट्रांसिरसीविंग सिस्टम (बी०टी०एस०) के सम्बन्ध में भवन के ढांचे की डिजायन तथा टावर के आधार से स्थायित्व और सुदृढ़ता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी०बी०आर०आई० रुड़की या आई०आई०टी०एन०, आई०आई०टी० या अन्य किसी संस्था के अधिकृत संरचना अभियन्ता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगी।
- (ड) किसी भवन की छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।
- (ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।
 - (ठ) कोई टावर भवन के विद्यमान एलाइनमेंट के बाहर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।
- (ड़) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना जिस पर यह प्रतिष्ठित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में संरक्षित रुप से संवितरित होगा।
- (ण) टावर की स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाये किन्तु जहां यह सम्भव न हो वहां यथा संभव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।
- (त) टावर पर लगा एन्टिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से 03 मीटर की ऊंचाई पर होगा।
- (थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर, अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 05 मी0 से कम हों) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था से 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किये जायेंगे।
- (द) टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एन्टिना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थित में टावर / बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नलिखित होगी।

7				
क्रमांक	गुणज एन्टीनों की संख्या	एन्टिना से बिल्डिंग / संरचना की दूरी (संरक्षित दूरी) मी० में		
1	2	35		
2	4	45		
3	6	55		
4	8	65		
5	10	70		
6	12	45		

- (घ) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसिमशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित करना होगा।
- (न) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टिना एक सामान्य जन की पहुंच को समुचित तरीके जैसे कटींले तार छत पर पहुंचने के दरवाजे अथवा बाउन्ड्रीवाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथा सम्भव कम से कम अविध के लिये टावर तक पहुंचने की अनुमित दी जायेगी।
- (प) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृश्यता होना चाहिए और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये—
 - 1-विकरण खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें।

2-प्रतिबन्धित क्षेत्र।

- (फ) सेवा / स्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडियेशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (ब) प्रत्येक सेवा / अवस्थापना प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बैरीकेटिंग टिन आदि लगा कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- (भ) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृश्यता में बाधा और व्यवधान उन्पन्न हो वहां टावर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
 - (म) जहां इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित हो वहां अनुमति देय नहीं होगी।
- (य) आवेदक द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (र) टावर की स्थापना मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।
 - (ल) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
- (व) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6-क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र

प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7-सम्पत्ति कर का आरोपण

टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के आधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा जो अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

8—अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण

अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने की दिनांक से अनिधक 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी।

9—टावर हटाने की शक्ति

यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, गाड़ा जाता है, लटकाया जाता है, या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशांति का कारण हो तो अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्न लिखित धनराशियों को बसूल सकता है।

(एक) टावर हटाये जाने का व्यय।

(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया, परिनिर्मित किया गया, खड़ा किया गया, गाड़ा गया के लिए हुई क्षति की धनराशि।

10-टावर का निर्बन्धन

किसी संविदा या अनुबन्धन में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्न लिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी—

- (क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।
- (ख) राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर से 20 मीटर के भीतर।
- (ग) अन्य मार्गों के यान मार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर।

- (घ) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों ऊपर।
 - (इ) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हो।
 - (च) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।
 - (छ) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

11-निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

नगर पंचायत राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

12—अनुरक्षण

- (1) सभी टावर जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है अवलम्बों बेंधनी रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगें जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्त्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे। 13–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज माप या नाप करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उसके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

- 14—शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति
- (1) इस निमित्त वार्षिक शुल्क और प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण नगर पंचायत गोहाण्ड द्वारा किया जायेगां जो नगर पंचायत सीमान्तर्गत रु० 20,000.00 (बीस हजार) तक प्रति टावर प्रति वर्ष होगी।
- (2) वार्षिक शुल्क एकल किस्त में देय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।
- (4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार, अथवा नगर पंचायत द्वारा जन सुविधाओं तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे, प्रकाश यन्त्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। 15–शक्ति और अपराधों का
- (1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की सिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के जिए जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है दण्डनीय होगा।
- (2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से न्यून और तीन चौथाई से अनाधिक वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनीता, अध्यक्ष, नगर पंचायत गोहाण्ड, हमीरपुर।

कार्यालय नगर पंचायत गोहाण्ड हमीरपुर अनुसूची

(नियम 4(1) दे	मूल्य खें)
1. आवेदक का नाम	
2. (एक) अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का न	пम
(दो) वेबसाइट (यदि कोई हो)	
3. पता (एक) अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था	
(दो) आवेदक का पता	
(तीन) दूरभाष संख्या	
(चार) ई-मेल आईडी	
4. आवेदित टावर का प्रकार	
5. टावर का आकार ऊंचाई सहित	
 स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थित 	
7. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी का नाम	
 (एक) स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखि 	त अनुमति संलग्न की जाये।
(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र कि चूक व भुगतान का उत्तर-दायीं होगा—संलग्न किया जाये।	र्ग दशा में टावर स्थापना हेतु देय समस्त शुल्कों के
(तीन) अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभि जाये।	।यन्ता द्वारा दी गई क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट संलग्न की
9. निर्धारित वार्षिक शुल्क—	रुपये
10. निर्धारित प्रतिभूति—	रुपये
11. अन्य विवरण	
संलग्नक	
स्थान	
दिनांक	आवेदक के हस्ताक्षर

नगर पंचायत गोहाण्ड, जनपद हमीरपुर

बस पार्किंग शुल्क नियमावली 31 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 827 / न0पं0गो0 / बस पार्किंग (2023-24) नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर नगर क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत चलने वाले वे समस्त प्रकार के वाहन जो मोटर से चलाये जाते हैं उनको विनियमित एवं नियन्त्रित करने के लिये पूर्व में बनाये गये बस पार्किंग उपनियम में संशोधन करके उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 293 (1) व 298 (2) जे0डी0 के अधीन दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उपनियम में संशोधन किया गया है, जिसका प्रकाशन समाचार-पत्र आज दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव मांगा गया था निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं अतः यह उपविधि म्यूनिस्पल एक्ट की धारा 301 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है जो गजट में मुद्रण तिथि से प्रभावी होगी।

उपनियम

1-संक्षिप्त नाम-

यह उपनियम नगर पंचायत गोहाण्ड के अन्तर्गत किराये पर चलने वाले मोटर-कार मोटर लारी, जीप, टैक्सी, टैम्पों, विक्रम मिनी बस, मिनी ट्रक, मोटर ठेला ट्रक, ट्रैक्टर को नियंत्रित करने हेतु बस पार्किग शुल्क वर्ष 2023-24 के नाम से जानी जायेगी।

2-प्रसार क्षेत्र

यह उपविधि नगर पंचायत गोहाण्ड की सीमा तथा उससे सन्निकट क्षेत्र 03 किमी की परिधि के अन्तर्गत होगी। 3—प्रस्तावना

- (1) यह कि परिवर्तित उपनियम प्रशासक की स्वीकृति के पश्चात तुरन्त लागू होगी।
- (2) कोई भी मोटर वाहन नगर पंचायत सीमा में 10 किमी प्रतिघंटा से अधिक तेज गति से नहीं चलाया जायेगा और न ही तेज आवाज वाला हार्न ही बजाया जायेगा।
- (3) किराये पर चलने वाले प्रत्येक टैक्सी, टैम्पों, विक्रम, कार, जीप, मिनी बस, ट्रैक्टर ट्राली इसी प्रकार मोटर से चलने वाले आदि वाहन मोटर लारी, ठेला आदि वाहन जो नगर पंचायत की सीमा क्षेत्र के भीतर बस पार्किंग अथवा नगर के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नगर पंचायत के द्वारा 03 किमी परिधि के भीतर किसी भी परिसर अथवा स्थान जहां जनता को प्रवेश की अनुमित हो यात्रियों को चढ़ायेगा अथवा उतारेगा अथवा सामान को चढ़ायेगा अथवा उतारेगा तो नगर पंचायत को प्रतिदिन नगर द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करेगा।
- (4) उक्त शुल्क की वसूली अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन की बसूली की जायेगी।
- (5) यह कि ठेका पार्किंग शुल्क नीलामी द्वारा / टेण्डर आमंत्रित करके उसकी स्वीकृति अध्यक्ष / बोर्ड द्वारा की जायेगी।
 - (6) ठेका पार्किंग शुल्क एक वर्ष के लिये होगा जिसकी अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
- (7) नीलाम होने की स्थिति में ठेका स्वीकृत होने पर ठेका की कुल धनराशि का 1/2 भाग (आधा) तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि छः माह में दो बराबर किस्तों में अदा करना होगा। ऐसा न करने पर बिना नोटिस दिये ही ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी को होगा।
- (8) ठेका स्वीकृत होने पर अथवा ठेका छोड़ने का अधिकार ठेकेदार को न होगा। ठेकेदार द्वारा बीच में ठेका छोड़ने की अवस्था में नगर पंचायत कोष में जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि पुनः नीलाम करने में प्रथम नीलाम की हुई धनराशि की अपेक्षा पंचायत को घाटा रहता है तो घाटे की अदायगी की जिम्मेदारी पहले ठेका

लेने वाले ठेकेदार की होगी जो न अदा करने की दशा में नियमानुसार उससे मालगुजारी की भांति वसूल करने का अधिकार अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी को होगा।

- (9) ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों को निर्धारित शुल्क से अधिक धन वसूल करने का अधिकार न होगा।
- (10) ठेकेदार अथवा उसका कोई कर्मचारी नियम विरुद्ध फीस बसूल करने की अवस्था में ठेकेदार उसका उतना ही दोषी होगा, जितना कि वह कर्मचारी और दोष सिद्ध होने पर रु० 500.00 तक जुर्माना बसूल होगा।
- (11) शर्तों के विपरीत कार्य करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और जो धनराशि ठेकेदार की पूर्व में जमा होगी वह नगर पंचायत के हित में जमा कर ली जायेगी।
- (12) ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को नगर पंचायत से रसीद का प्रारुप प्राप्त करके रसीद छपवाना होगा और उन रसीदों पर नगर पंचायत से मोहर लगवाकर ही पार्किंग शुल्क की वसूली की जायेगी।
- (13) यदि कोई मोटर कार, जीप, मोटर लारी टैक्सी मिनी बस या मोटर से चलने वाले अन्य वाहन मोटर ठेला, ट्रैक्टर ट्राली या इसी प्रकार के अन्य वाहन अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत या ठेकेदार के द्वारा फीस मांगने पर यदि उसे नहीं देगा तो वह उपनियम की धारा 3 का दोषी होगा और उस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
- (14) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, कर्मचारी नगर पंचायत या ठेकेदार का मुतालबा बसूल करने में बाधा पहुंचायेगा तो वह यू०पी० म्यूनिसिपालिटीज एक्ट 1916 की धारा 294 का दोषी होगा। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के अनुसार भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (15) ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को नगर पंचायत के हित में वांछित स्टाम्प पेपर पर स्टाम्प एक्ट के अनुसार स्टाम्प पेपर जमा करके ठेकेनामा तहरीर करेगा।
 - (16) ठेकेदार ठेकेनामा तहरीर के बाद ही चार्ज ठेका व बसूली का हकदार होगा।
 - (17) बस पार्किंग शुल्क के अतिरिक्त वाहनों से अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

बस पार्किंग शुल्क की प्रस्तावित दरें

क्र0 सं0	नाम	छरें
		₹ 0
1	टैक्सी, टैम्पू आटो रिक्शा, जीप कार सवारी उतारने चढ़ाने पर	40
2	मिनी बस, मिनी ट्रक पर सवारी / सामग्री उताने चढ़ाने पर	100
3	ट्रैक्टर ट्राली लोडिंग/अनलोडिंग	30
4	मोटर कार, टैक्सी, जीप प्रचार हेतु	30
5	गुम्मा, सीमेन्ट ईंटा, बालू, गिटटी सब्जी गल्ला आदि से लदा ट्रक जो माल उतारे अथवा चढ़ाये	60
6	ट्रांसपोर्ट का ट्रक जो विभिन्न व्यापारियों का माल चढ़ाये या उतारे	100
7	कबाड़ लादने वाला ट्रक एवं डीजल, पेट्रोल मिटटी के तेल आदि के टैंकर की लोडिंग/अनलोडिंग पर	50
8	प्राईवेट मोटर बस, डबल डेकर बस जो नगर पंचायत की सीमा के निर्धारित परिधि के अन्दर रुककर यात्री उतारने एवं चढ़ाने की दशा में।	120

शास्ति

यू०पी०म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत गोहाण्ड यह निर्देश देती है कि इस नियमावली में दिये गये किन्हीं उपबन्धों की अवहेलना करने पर अर्थदण्ड का भागी होगा जो रु० 1,000.00 तक हो सकता है और उल्लंघन जारी रखने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा। जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसने अपराधी अपराध करता रहा है। रु० 25.00 तक हो सकता है।

अनीता, अध्यक्ष, नगर पंचायत गोहाण्ड, हमीरपुर।

कार्यालय नगर पंचायत गोहाण्ड, हमीरपुर

21 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 735 / विविध शुल्क उपविधि / न0पं0गो0 / 2023—24—उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचयात गोहाण्ड जनपद हमीरपुर के सीमा हेतु "विविध कर(शुल्क) उपविधि नियमावली—2017" प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला दिनांक 29 नवम्बर 2023 ई० को प्रकाशन कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव मांगा गया था निर्धारित अविध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं अतः यह उपविधि म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 301 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। जो गजट में मुद्रण तिथि से प्रभावी होगी।

"विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2017"

1-संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ-

- 1-यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली २०१७ कहलायेगी।
- 2-यह नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवृत्त होगा।
- 3—यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर में प्रवृत्त होगा।

2-परिभाषायें-

विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढा व समझा जाये।

- 1-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।
- 2—अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर के अधिशासी अधिकारी से है।
- 3-नगर पंचायत गोहाण्ड का तात्पर्य नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर से है।
- 4—अध्यक्ष / प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर के अध्यक्ष / प्रशासक से है। 3—विविधकर (शुल्क) की दर—
 - 1-प्रमाण-पत्र शुल्क रु० १०० / -(द्वितीय प्रति शुल्क रु० २०० / तृतीय प्रति शुल्क रु० ३०० / -प्रमाण-पत्र)।
 - 2-जलापूर्ति टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत की सीमा में सार्वजनिक कार्य हेतु) रु० ५०० (पॉच सौ मात्र)।

- 3—जलापूर्ति टैंकर शुल्क (नगर पंचायत सीमा के बाहर अधिकतम 10 किमी० तक केवल सार्वजनिक कार्य हेतु रू० 1,000/— (एक हजार) प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।
- 4—सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु० २,०००.०० (दो हजार) प्रति चक्कर / प्रथमवार (द्वितीय चक्कर) रु० 1,०००.०० (एक हजार)।
- 5—सीवरेज टैंकर शुल्क (नगर पंचायत सीमा क बाहर अधिकतम 10 किमी० तक) रु० 2,500.00 (दो हजार पांच सौ) प्रति चक्कर / प्रति टैंकर (द्वितीय चक्कर) रु० 1,500.00 (एक हजार पॉच सौ)।
- 6—नाला / नाली या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 100.00 (एक सौ मात्र) प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 500.00 (पॉच सौ मात्र) प्रतिप्रकरण।
- 7—40 माइक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पॉलिथिन प्रयोग करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 100.00 (एक सौ मात्र) प्रति प्रकरण तथा 40 माइक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पालिथिन प्रयोग करने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 (पॉच सौ मात्र) प्रतिप्रकरण।
 - 8—नगर पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यवसायिक शुल्क रु० २,०००.०० (दो हजार) वार्षिक।
- 9—नगर पंचायत सीमा में व्यावसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट / ढाबा / होटल पर व्यावसायिक शुल्क रु० 1,000.00 (एक हजार मात्र) / वार्षिक।
 - 10-नगर पंचायत सीमा में चलने वाले ई-रिक्शा / गाडी पर लाइसेंस शुल्क रु० ३००.०० (तीन सौ) / वार्षिक।
- 11—नगर पंचात सीमा में स्थित आटा चक्की/धान कूटने वाली मशीन/तेल पेराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु० 500.00 (पांच सौ)/वार्षिक।
 - 12-नगर पंचायत में अधिष्ठापित बिजली के ट्रांसफार्मर पर शूल्क रु० 1,000.00 (एक हजार)/ वार्षिक।
- 13—नगर पंचायत में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु० 5,000.00 (पांच हजार)/वार्षिक।
- 14—भैंस / गाय / सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवर को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु० 300.00 (तीन सौ) प्रति प्रकरण / प्रतिदिन।
- 15—नगर पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचायल के टॉयलेट प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से रु० 3.00 (तीन) प्रति व्यक्ति एवं बाथरूम प्रयोक्ता चार्ज रु० 5.00 (पांच) व्यक्ति लिया जायेगा।
- 16—नगर पंचायत गोहाण्ड में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 1,000.00 (एक हजार) तथा पुनरावृत्ति करने पर रु० 5,000.00 (पांच हजार) प्रकरण।
- 17—नगर पंचायत में स्थित व व्यवसाय करने वाले चाय, पेटी, गुमटी छोटे दुकानदारों पर व्यवसायिक शुल्क रु० 500.0 (पांच सौ) वार्षिक व मध्यम वर्ग के दुकानदारों पर व्यवसायिक शुल्क रु० 750.00 (सात सौ पचास) तथा बड़े दुकानदारों पर व्यवसायिक शुल्क रु० 1,000.00 (एक हजार)/वार्षिक।
- 18—छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पडोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकने को दष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा अपने खली भू-खण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीबाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु० 1,000.00 (एक हजार)।
 - 19—नगर पंचात सीमा में स्थित राइस मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु० ४,०००.०० (चार हजार)/वार्षिक।
 - 20—नगर पंचायत सीमा में स्थित आरा मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु० २,०००.०० (दो हजार)/ वार्षिक।

21—नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी / प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु० 500.00 (पांच सौ) / वार्षिक।

22—नगर पंचायत सीमा में आर0ओ० प्लांट पर व्यावसायिक शुल्क रु० २,०००.०० (दो हजार)/ वार्षिक।

23—नगर पंचायत सीमा में मोटर साइकिल एजेन्सी/कार एजेन्सी/ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 (पांच हजार)/वार्षिक।

24—नगर पंचायत सीमा में गलियों में बांधे गये जानवरों को पकड़े जाने पर शुल्क रु० 50.00 (पचास) प्रति प्रकरण।

25—नगर पंचायत सीमा से इमारत कर सूची में भवन नामान्तरण (दाखिल-खारिज) शुल्क रु० 1,000.00 (एक हजार) प्रति प्रकरण।

26—नगर पंचायत सीमा से बाहर की भूमि से संबंधित अनापति प्रमाण-पत्र शुल्क रु० 500.00 (पांच सौ) प्रति प्रकरण।

27—नगर पंचायत सीमा में स्थित सार्वजानिक हैण्ड पम्प में समरसेविल डालने पर शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) प्रति प्रकरण।

28—डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु प्रतिदिन रु० २.०० प्रति घर।

उक्त धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा में रु० 5000.00 (पांच हजार) जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें अपराधी द्वारा उपराध किया जाना सिद्ध होता है, रु० 50.00 (पंचास) तक होगा।जुर्माना लगाये जाने व छूट दिये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोहाण्ड जनपद हमीरपुर में निहित होगा तथा वसूली नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 6 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

अनीता, अध्यक्ष, नगर पंचायत गोहाण्ड, हमीरपुर।

सूचना

सूचित किया जाता है, मेरा सही नाम राम चन्द्र सिंह (RAM CHANDRA SINGH) पुत्र सहदेव सिंह है जो मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेख, ECHS कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरा नाम राम चन्दर सिंह (RAM CHANDAR SINGH) पुत्र सहदेव सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राम चन्द्र सिंह (RAM CHANDRA SINGH) पुत्र सहदेव सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

राम चन्द्र सिंह, ग्राम-जयन्तीपुर,पोस्ट-चम्पहा बाजार, जिला-कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुष्का वर्मा पुत्री अमेरिका कुमार वर्मा है, जो मेरे शैक्षिणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 6990 7899 7600 में नाम शगुन वर्मा अंकित है, जो मेरा घरेलू नाम है, दोनों नाम मेरा ही है, भविष्य में मुझे अनुष्का वर्मा पुत्री अमेरिका कुमार वर्मा, वार्ड नं0 11 तिलक नगर, निकट काली मन्दिर हाटा, कुशीनगर के नाम से जाना व पहचाना जायें।

अनुष्का वर्मा।

सूचना

मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक-5153800 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक-216420298 के अंक प्रमाण-पत्र में मेरी माता का नाम आशा गुप्ता गलत अंकित हो गया है। जबिक मेरी माता के आधार कार्ड, पैन कार्ड के अनुसार उनका सही नाम पुजा गुप्ता है। अंशिका गुप्ता पुत्री संजय कुमार गुप्ता निवासिनी- 555क/38 कनौसी, मानक नगर लखनऊ।

अंशिका गुप्ता।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम महेन्द्र कुमार मिश्र है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक 23244420) में मेरा नाम अनन्द मिश्रा (ANAND MISHRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। महेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 राधेश्याम मिश्रा ग्रा०-बेदौली, पो० सिरसा, तहसील मेजा, जिला, प्रयागराज (उ०प्र०)।

महेन्द्र कुमार मिश्रा।

सूचना

सर्वसाधाराण को सूचित किया जात है कि पंजीकृत फर्म M/s. THE REX INFRA STATE 31/28 A, Badi Bagiya Lala Ki Sarai, Civil Lines, Prayagraj के भागीदार मो0 इरफान दिनांक 03 फरवरी, 2024 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये है तथा नवामी कुमारी दिनांक 03 फरवरी, 2024 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुई है। अब फर्म में भागीदारों की भागीदारी का अनुपात क्रमशः प्रभात कुमार का 75 प्रतिशत एवं नवामी कुमारी का 25 प्रतिशत होगा फर्म से अलग हुए भागीदार मो0 इरफान का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दियत्व शेष नहीं है।

भागीदार, प्रभात कुमार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयांश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3981 6610 5372 में उसका नाम आशु कुमार अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है भविष्य में मेरे पुत्र को अयांश कुमार पुत्र विमलेश कुमार पाल के नाम से जाना और पहचाना जाये। पता-विमलेश कुमार पाल, ग्राम दौलतपुर पोस्ट छिबैंया झूँसी, जनपद-प्रयागराज, उ०प्र0 211009।

विमलेश कुमार पाल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री को सही नाम अवनी द्विवेदी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 8333 7080 2971 में मेरी पुत्री का नाम पलक द्विवेदी अंकित हो गया है। जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को अवनी द्विवेदी पुत्री शशिकान्त द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

> शशिकान्त द्विवेदी, पता-एन-11 / 58के, रानीपुर महमूरगंज, छितपुर वाराणसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री सुरिम इण्डस्ट्रीज आर0/ओ0 फ्लैट नं0-208 सर्राफ रेजीडेंसी वार्ड 33 बेतियाहाता, जनपद गोरखपुर, उ०प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 25 अगस्त, 2020 से श्री चैतन्य अग्रवाल एवं श्रीमती पूनम अग्रवाल जी साझेदार थे। यह की साझेदारी डीड दिनांक 03 फरवरी, 2024 से श्री चैतन्य अग्रवाल पुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती पूनम अग्रवाल पुत्री श्री विनोद नेमानी जी उक्त फर्म से रिटायर्ड हो चुके है एवं श्री सुमित रूंगटा पुत्र शिव कुमार रूंगटा व् श्रीमती प्रभा रूंगटा पत्नी श्री सुमित रूंगटा जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुई है, यह कि उक्त फर्म का पता-7 फ्लोर गैलेंट लैंडमार्क बैंक रोड जनपद गोरखपुर, उ०प्र0 से परिवर्तित कर आर/ओ0 फ्लैट नं 208 सर्राफ रेजीडेंसी

वार्ड 33 बेतियाहाता, जनपद गोरखपुर, उ०प्र० किया गया है अब उक्त फर्म में साझेदार श्री सुमित रूंगटा एवं श्रीमती प्रभा रूंगटा जी है। किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

> साझेदार, सुमित रूंगटा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मेसर्स टेकुटार पोल्ट्री फार्म, गोपाल भवन जज़ेज कम्पाउण्ड, सिविल लाइन्स जनपद-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की साझेदारी दिनांक 17 मार्च, 2023 को भंग हो गयी है। फर्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई बकाया या विवाद नहीं है। धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व० शिव कुमार सिंह गोपाल भवन जज़ेज-कम्पाउण्ड सिविल लाइन्स, जनपद गोरखपुर, उ०प्र०।

साझेदार, धर्मेन्द्र सिंह, मेसर्स टेकुआटार पोल्ट्री फार्म, गोरखपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मनीष सिंह, रविन्द्र भवन टाउन हॉल जनपद गोरखपुर, उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 जनवरी, 2023 से श्री पंकज सिंह, श्री मनीष सिंह व भानु प्रताप मल्ल एवं कुलदीप प्रताप शाही साझेदार है। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म, सोसाइटीज एवं चिट्स 'जनपद गोरखपुर, में पंजीकरण सं० जी3637 पर पंजीकृत है। यह कि साझेदारी डीड दिनांक 09 फरवरी, 2024 से उक्त फर्म का नाम मेसर्स मनीष सिंह से परिवर्तित कर मेसर्स एम०एस० एसोसिएट्स कर दिया गया है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

साझीदार, पंकज सिंह, मेसर्स एम0एस0 एसोसिएट्स, रविन्द्र भवन, टाउन हॉल, जनपद गोरखपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s. Healthy Hens Agro Products, 26G, New Shiv Lok, Dr. Karoli Road, Begum Bag Meerut-250001 कि साझीदारी में श्री अफजाल अली मो० तारिक, श्री नवाजिश शहिद, श्री वसीम अहमद, श्री फुजल हुसैन साझीदार थे। दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 को श्री ताबिश अहमद एवं श्री शमशाद फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा श्री मौo तारिक एवं श्री वसीम अहमद फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये है। दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री अफजाल अहमद, श्री नवाजिस शाहिद, श्री फुजल हुसैन, श्री ताबिश अहमद एवं श्री शमशाद साझीदार है तथा फर्म का पता Khasra No. 379, Village-Morna, Tehsil-Sadar, District-Meerut-250002 हो गया है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

> साझीदार, अफजाल अली, M/s. Healthy Hens Agro Products, Khasra No. 379, Village-Morna, Tehsil-Sadar, District-Meerut-250002.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मैसर्स महालक्ष्मी लैण्डमार्क, 710 / 711, कोठी नं0-1, दीक्षित हाउस, सोतीगंज, मेरठ—250002 की साझीदारी में श्री चन्द्र विशाल त्यागी, मौहम्मद तारिक, श्री फुजैल हुसैन एवं श्री अफजल अली साझीदार थे। दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को मौहम्मद तारिक फर्म की साझीदारा से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये है। दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री चन्द्र विशाल त्यागी, श्री फुजैल हुसैन एवं श्री अफजाल अली साझीदार है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

साझीदार, अफजाल अली, मैसर्स महालक्ष्मी लेण्डमार्क, 710 / 711, कोठी नं0-1, दीक्षित हाउस, सोतीगंज, मेरठ-250002।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मै0 वर्टेक्स एक्सपोर्टस, सी-241 सेक्टर-II ताला नगरी, रामघाट रोड, अलीगढ में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह है कि फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को फर्म के चतुर्थ साझेदार श्री तुषार सिंघल पुत्र श्री आलोक कुमार सिंघल निवासी-406 स्क्वेयर टावर मैरिस रोड, अलीगढ फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री आलोक कुमार सिंघल, श्रीमती वन्दना सिंघल तथा श्री रोहन सिंघल साझेदार है।

> आलोक कुमार सिंघल, साझेदार, फर्म मै0 वर्टेक्स एक्सपोर्टस, सी-241 सेक्टर-II ताला नगरी, रामघाट रोड, अलीगढ।

सूचना

फर्म मैसर्स लक्ष्मीनारायन हरेश कुमार, कौशलपुर विद्या नगर, आगरा पत्रावली संख्या AGR-0009975 में दिनांक 25 अगस्त, 2021 से हम लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र डा० कमल प्रसाद शर्मा, निवासी- समीप अन्नपूर्णा पब्लिक स्कूल, कौशलपुर, विद्या नगर, आगरा प्रथम पक्ष व श्री हरेश शर्मा पुत्र, श्री भगवान शर्मा निवासी-26/223 अहीरपाडा, बल्का बस्ती लोहामण्डी, वार्ड शहर आगरा द्वितीय पक्ष द्वारा साझेदारी के अंतर्गत संचालित की थी, किन्तु दिनांक- 01 अप्रैल, 2023 को दोनो पक्षों की आपसी सहमति से फर्म विघटित की जाती है।

साझेदार लक्ष्मी नारायण शर्मा, मैसर्स लक्ष्मीनारायन हरेश कुमार, कौशलपुर विद्या नगर, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स लाला केशव देव आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, 146-बी, गुप्ता कालानी, सादाबाद रोड़, राया जिला मथुरा परिवर्तित पता- ग्राम मदैम छीकड़ा, पोस्ट मदैम सादाबाद, रोड़ राया, जिला-मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है— यह कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को फर्म के भागीदार श्री निशान्त गोयल पुत्र श्री राम किशोर गोयल, श्रीमती पूजा गोयल पत्नी श्री निशान्त गोयल तथा श्री राम किशोर गोयल पुत्र श्री निशान्त गोयल तथा श्री राम किशोर गोयल पुत्र श्री निरोत्तम दास, निवासी-म0नं0-68 वार्ड नं0-11, ग्राम हसनपुर, होडल, फरीदाबाद फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं अब फर्म में श्री मुकुल अग्रवाल, श्री हरिओम अग्रवाल, श्री मयंक अग्रवाल, श्रीमती अन्जली अग्रवाल तथा श्री शुभम अग्रवाल ही भागीदार रह गये है।

भागीदार, मुकुल अग्रवाल, मै0 लाला केशव देव, एण्ड कोल्ड स्टोरेज, 146-बी, गुप्ता कालेानी, सादाबाद रोड़ राया, जिला मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम गुरदेव सिंह (GURDEV SINGH) है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट पर अंकित है—

त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के सह अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक 23160390) तथा इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक 23649001) में मेरे पिता का नाम GURE DAVE SINGH अंकित हो गया है जो कि गलत है।

हरमनदीप सिंह, पुत्र गुरदेव सिंह, निवासी-वार्ड नं0-4 बुद्ध नगर, बुधाया खुर्द सुकरौली, कुशीनगर उ०प्र0-274207।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स टेकुआटार फर्म एण्ड फार्मुलेशनस्, गोपाल भवन, जजेज कम्पाउन्ड, जनपद गोरखपुर, उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं० G-5202 पर पंजीकृत है। साझेदारी डीड दिनांक 17 मार्च, 2023 से श्री ध्यानेन्द्र सिंह जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए है यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 25 मार्च,

2023 से श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके है। उक्त फर्म में क्रमशः श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं श्री ध्यानेन्द्र सिंह जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नही है।

साझेदार, धर्मेन्द्र सिंह, मेसर्स टेकुआटार फर्म एण्ड फार्मुलेशनस्, गोपाल भवन, जजेज कम्पाउन्ड, जनपद गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मैसर्स ''नूर मोटर्स'' माठखेड़ा रोड, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को मुर्शीद अली पुत्र श्री बन्दे अली निवासी संतनगर, कॉलोनी तहसील बिलासपुर, जिला-रामपुर, उत्तर प्रदेश। त्यागपत्र दिनांक 01 अप्रैल 2023 से अलग हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को अमन मुर्शीद पुत्र श्री मुर्शीद अली निवासी संत नगर, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश पार्टनर के रूप में शामिल हो गए है। तथा उक्त फर्म पर अलग हुऐ पार्टनर की कोई लेनदारी व देनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्रीमती उषा उर्फ् आयशा एवं अमन मुर्शीद रह गए है।

पार्टनर, अमन मुर्शीद, नूर मोटर्स'' माठखेड़ा रोड, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, मेरा सही नाम शिवा कोठारी पुत्री स्व० वी०पी० कोठारी है जो मेरे अभिलेखों, पैन कार्ड, आधार कार्ड में अंकित है। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैंने अपना नाम शिवा कोठारी से बदलकर शीबा रख लिया है। भविष्य में मुझे शीबा पुत्र वी०पी० कोठारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शिवा कोठारी, एल0आई०जी० 298, ए०डी०ए०, कालोनी, प्रीतम नगर, प्रयागराज।

NOTICE

In my High School Result Roll No. 23252378, Year 2023 of CBSC Board my parent's name wrongly written as SHAIKH HASHMAT ULLAH & ANIESA BEGUM which is wrong. As per Aadhar Card my parent's correct name is HASHMAT ULLAH & ANISHA BEGAM.

Shaikh Hamza, S/o Hashmat Ullah, R/o-D-1088, G.T.B. Nagar, Kareli, Prayagraj.